शनिवार 23 अगस्त 2025
सूर्योदय प्रातः 05:55 बजे
सूर्यास्त सायं 18:53 बजे

www.khabariya.com

एनसीआर टुडे

करंट न्यूज करंट व्यूज

पृष्ठ 4 पंजाब में फंस रही है आम आदमी पार्टी

उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एक साथ प्रकाशित | वर्ष: 16 | अंक: 308 | गाजियाबाद, शनिवार 23 अगस्त 2025 | मूल्य: ₹ 2 | पेज: 06 | विक्रमी संवत् 2081 | युगाब्द 5126 | शाक 1946

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की

✷ **एनसीआर टुडे. नई दिल्ली** ✷। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने शुक्रवार को यहां राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अंतरिक्ष में अपने अनुभव साझा किए। यह जानकारी राष्ट्रपति के कार्यालय ने दी। शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। वह अन्य साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक्सिओम मिशन 4 के तहत 20 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के बाद पिछले महीने पृथ्वी पर लौटे हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर और ग्रुप कैप्टन पुण्यश्लोक बिस्वाल, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी नारायणन और मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक दिनेश कुमार सिंह ने मुर्मू से मुलाकात की। उन्होंने अंतरिक्ष में अपने अनुभव राष्ट्रपति के साथ साझा किए।

संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, युवक को दबोचा

✷ **एनसीआर टुडे. नई दिल्ली** ✷। संसद भवन की सुरक्षा में एक बार फिर सेंध लगाने की कोशिश हुई। सुरक्षाकर्मियों ने संसद भवन की सीमा दीवार के पास शुक्रवार सुबह करीब 5.50 बजे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे एक युवक को पकड़ा। नई दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार महला ने बताया कि पकड़े गए युवक की पहचान राम (20) के रूप में हुई है। वह मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है। वह अपना नाम भी सही तरह से बता नहीं पा रहा है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने का एक मामला सामने आया था। उस दौरान संसद की कार्यवाही के दौरान कुछ लड़के संसद भवन में घुस गए थे।

दलाई लामा का उत्तराधिकारी : सरकार ने कहा, धार्मिक मान्यताओं से जुड़े मामलों पर पक्ष नहीं रखती

✷ **एनसीआर टुडे. नई दिल्ली** ✷। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने दलाई लामा की संस्था के बारे में 14वें दलाई लामा द्वारा जुलाई में जारी बयान को देखा है। इसके साथ ही उसने रेखांकित किया कि भारत सरकार आस्था एवं धार्मिक मान्यताओं से जुड़े मामलों पर कोई पक्ष नहीं रखती है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तवर्धन सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में बृहस्पतिवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी। उनसे सवाल किया गया था, ''क्या यह सच है कि सरकार ने दलाई लामा के अपने उत्तराधिकार पर स्वयं निर्णय लेने के अधिकार का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया है?'' इसके जवाब में विदेश राज्य मंत्री सिंह ने कहा, ''सरकार ने दलाई लामा की संस्था के संबंध में 14वें दलाई लामा द्वारा दो जुलाई 2025 को जारी वक्तव्य देखा है।

कोर्ट ने असम में दर्ज मामले में पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर को गिरफ्तारी से राहत

✷ **एनसीआर टुडे. नई दिल्ली** ✷। सुप्रीम कोर्ट ने एक समाचार लेख को लेकर वेब पोर्टल 'द वायर' के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन और सलाहकार संपादक करण थापर के खिलाफ असम पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के संबंध में शुक्रवार को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म (एफआईजे) की याचिका पर आदेश सुनाया। एफआईजे वरदराजन के साथ 'द वायर' का स्वामित्व रखता है।

बिहार एसआईआर में आधार को मिली मान्यता

मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को आधार या 11 दस्तावेजों के साथ दावे दर्ज कराने की अनुमति

✷ **एनसीआर टुडे. नई दिल्ली** ✷

उच्चतम न्यायालय ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान बाहर हुए व्यक्तियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपने दावे दर्ज कराने की अनुमति देने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने आधार कार्ड संख्या और एसआईआर में स्वीकार्य 11 दश्तावेजों में से किसी एक के साथ दावा प्रपत्र प्रश्तुत करने की अनुमति दी।

शीर्ष अदालत ने 65 लाख व्यक्तियों के मतदाता सूची से बाहर होने से संबंधित मामले में आपत्तियां दर्ज कराने के लिए राजनीतिक दलों के आगे नहीं आने पर आश्चर्य व्यक्त किया। न्यायालय ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया कि वह अदालती कार्यवाही में राजनीतिक दलों को भी पक्षकार बनाएं। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए आठ सितंबर की तारीख तय करते हुए कहा, 'सभी राजनीतिक दल अगली सुनवाई तक उस दावा प्रपत्र के बारे में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करेंगे, जिसे दाखिल करने में उन्होंने मतदाता सूची से बाहर हुए व्यक्तियों की मदद की थी।' पीठ ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मतदाता सूची से बाहर हुए व्यक्तियों के दावा प्रपत्र भौतिक रूप से जमा कराने वाले राजनीतिक दलों के बूथ श्तर के एजेंटों को पावती रसीद उपलब्ध कराएं।

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने न्यायालय से आग्रह किया कि वह चुनाव आयोग को यह दिखाने के लिए 15 दिन का समय दे कि कोई भी नाम सूची से बाहर नहीं किया गया है।

द्विवेदी ने कहा, 'राजनीतिक दल शोर मचा रहे हैं। हालात खराब नहीं हैं। हम पर विश्वास रखें और हमें कुछ और समय दें। हम आपको दिखा देंगे कि कोई भी छूटा नहीं है।'

आयोग ने पीठ को बताया कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए लगभग 85,000 मतदाताओं ने अपने दावापत्र प्रश्तुत किए हैं और राज्य में एसआईआर के तहत दो लाख से अधिक नए व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आगे आए हैं।

शीर्ष अदालत ने 14 अगश्त को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण 19 अगश्त तक प्रकाशित करे।

पीठ ने कहा था कि निर्वाचन आयोग को अपने ख़िलाफ़ 'गढ़े जा रहे विमर्श' को खत्म करना चाहिए। पीठ ने यह आदेश भी दिया था कि विवरण में मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सूची से लोगों के नाम हटाने के कारण भी शामिल होने चाहिए।

कांग्रेस की मान्यता रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका

✷ **एनसीआर टुडे. नई दिल्ली** ✷

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बिहार एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई है। इससे ठीक पहले एक अहम जनहित याचिका ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल ने चुनाव आयोग के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाली कांग्रेस की मान्यता रद्द कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली है।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर और गैर जिम्मेदाराना हैं। इन दोनों ने एक संवैधानिक संस्था की साख को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है और ऐसे में न सिर्फ पार्टी की मान्यता रद्द हो बल्कि इनके दुष्प्रचार की जांच एसआईटी से कराई जाए।

दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान के प्रति वफादारी की शपथ को तोड़ा है। याचिका में कुछ नियमों का हवाला दिया गया है। कहा गया है कि कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय भारत के संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखने की शपथ ली थी।

हालांकि, ईसीआई के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान इस शपथ का उल्लंघन करता है और आयोग के कार्यों को गैरकानूनी तरीके से बाधित करने की कोशिश कर रहा है। नियमों का हवाला देते हुए पीआईएल कहती है- निर्वाचन आयोग को देशभर में मतदाता सूची तैयार करने और संशोधन करने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित केवल 38.8 फीसदी काम हुआ

✷ **एनसीआर टुडे. नई दिल्ली** ✷

राज्यसभा की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी और एक महीने तक चले सत्र के दौरान हंगामे के कारण ज्यादातर समय कार्यवाही बाधित रही तथा केवल 38.88 प्रतिशत कामकाज हो सका।

इसके साथ ही 21 अगश्त को शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया। उप सभापति हरिवंश ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले अपने समापन वक्तव्य में सदस्यों की टोका-टोकी के बीच कहा कि 268 वें सत्र के दौरान सदस्यों के हंगामे के कारण कुल मिलाकर सदन केवल 41 घंटे 15 मिनट ही चला। उन्होंने कहा कि इस सत्र में केवल 38.88 प्रतिशत कामकाज हुआ जो निराशाजनक है और इस पर गंभीर आत्मनिरीक्षण किये जाने की जरूरत है। सत्र के दौरान सदस्यों को 285 प्रश्न, 285 शून्यकाल विषय और 285 विशेष उल्लेख उठाने का अवसर था लेकिन केवल 14 प्रश्न, 7 शून्यकाल विषय और 61 विशेष उल्लेख ही वाश्तव में लिए जा सके जो सदन की पूरी क्षमता से कार्य करने की क्षमता का एक अंश मात्र हैं।

उप सभापति ने कहा कि सूचीबद्ध कार्यों पर सार्थक और व्यवधान-रहित चर्चा सुनिश्चित करने के लिए आसन के प्रयासों के बावजूद यह सत्र खेदजनक रूप से बार-बार व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

उन्होंने कहा कि इससे न केवल बहुमूल्य संसदीय समय की हानि हुई, बल्कि हमें सार्वजनिक महत्व के कई मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का अवसर भी नहीं मिला।

PM ने एसआईआर, 130वें संविधान संशोधन के विरोध के लिए 'इंडिया' गठबंधन को आड़े हाथ लिया

✷ **वेबवार्ता. गया जी (बिहार)** ✷

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) पर आरोप लगाया कि वह सत्ता के उच्च श्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों का और देश की जनसांख्यिकी के समक्ष घुसपैठियों से उत्पन्न खतरे से निपटने के लिए किए गए उपायों का विरोध कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने गयाजी में एक रैली में इस सप्ताह लोकसभा में अपनी सरकार द्वारा पेश किए गए संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 और बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान में किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख किया।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि दोनों विपक्षी दल संविधान (130वां संशोधन) विधेयक के खिलाफ हैं क्योंकि उनके अधिकतर नेता या तो जेल में हैं या जमानत पर हैं।

लोकसभा में बुधवार को संविधान (130वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया था जिसे संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। इसमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रश्ताव है।

उन्होंने परोक्ष रूप से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र करते हुए कहा, ''हमने एक खेदजनक स्थिति देखी है जिसमें सत्ता में बैठे लोग जेल से सरकार चला रहे हैं, सलाखों के पीछे से फाइलों पर हश्ताक्षर कर रहे हैं, संवैधानिक मर्यादा की धज्जियां उड़ा रहे हैं।''

मोदी ने दावा किया कि उनकी 11 साल की सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों में सामने आए अनेक घोटालों का भी जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, ''इसलिए हमने एक ऐसा कानून लाने का फैसला किया, जिसके

तहत अगर कोई भ्रष्ट मुख्यमंत्री या यहां तक कि प्रधानमंत्री 30 दिन जेल में बिताता है तो उसे बर्खाश्त किया जा सकता है। अगर कोई मामूली क्लर्क थोड़े समय के लिए भी जेल में रहता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन जब हम एक कड़ा कानून लेकर आए तो राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल भड़क गए। वे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें अपने पापों की सजा मिलने का डर है।'' उन्होंने कहा, ''कांग्रेस और राजद ने सत्ता में रहते हुए जनता के पैसे से अपनी तिजोरियां भरीं। इस उद्देश्य से, वे परियोजनाओं को अंतहीन रूप से लटकाए रखते थे। इसके विपरीत, मैं आज उस पुल का उद्घाटन कर रहा हूं जिसका शिलान्यास मैंने कुछ साल पहले ही किया था।''

मोदी ने आरोप लगाया, ''एक और खतरा है जो हमारे देश के सामने है- घुसपैठियों का। इस बारे में मैंने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी बात की थी। उन्हें हमारे देश के संसाधनों में हिस्सेदारी की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए, मैंने एक जनसांख्यिकीय मिशन की घोषणा की है। लेकिन कांग्रेस और राजद अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इन घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं।''

उनका इशारा एसआईआर की ओर माना जा रहा है, जिसका एक घोषित उद्देश्य 'बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमा से आए अवैध प्रवासियों' के नाम मतदाता सूची से हटाना है।

ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के बाद फैंटेसी ऐप्स ने लगाई रोक

✷ **एनसीआर टुडे. नई दिल्ली** ✷

ड्रीम स्पोर्ट्स, गेम्सक्राफ्ट, मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) और ज़ूपी जैसी भारत की प्रमुख रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) कंपनियों ने सरकार द्वारा 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025' पारित किए जाने के बाद, अपने प्लेटफॉर्म पर रियल मनी वाले खेलों पर रोक लगा दी है।

इस बिल ने उन सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जहां प्लेयर्स वित्तीय लाभ की उम्मीद में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा, इसने अधिकारियों को किसी भी परिसर की तलाशी लेने और उल्लंघन के संदेह में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार दिया है।

ड्रीम स्पोर्ट्स ने अपने नए फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप ड्रीम पिक्स और अपने कैजुअल आरएमजी ऐप ड्रीम प्ले पर सभी 'पे टू प्ले' कॉन्टेस्ट पर रोक लगा दी है। फैंटेसी स्पोर्ट्स की इस दिग्गज कंपनी ने हाल के महीनों में दोनों ऐप लॉन्च किए हैं। ऐप पर जारी एक नोटिस के अनुसार, "प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से संबंधित हालिया घटनाक्रम को देखते हुए, हम अपने प्लेटफॉर्म पर सभी 'पे टू प्ले' फैंटेसी स्पोर्ट्स कॉन्टेस्ट को रोक रहे हैं। आपका अकाउंट बैलेंस सुरक्षित है और आप ड्रीम11 ऐप से पैसे निकाल सकते हैं।" बोर्ड गेम्स पर केंद्रित एक अन्य आरएमजी प्लेटफॉर्म, ज़ूपी ने घोषणा की है कि उसने प्लेटफॉर्म पर सभी 'पेड गेम्स' को सस्पेंड कर दिया है। ज़ूपी के एक प्रवक्ता ने कहा, "ज़ूपी पूरी तरह से चालू रहेगा और हमारे प्लेयर्स प्लेटफॉर्म पर अपने पसंदीदा गेम्स का आनंद लेना जारी रख सकते हैं। नए ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुरूप, हम पेड गेम्स बंद कर रहे हैं, लेकिन लूडो सुप्रीम, लूडो टर्बो, स्नेक्स एंड लैडर्स और ट्रंप कार्ड मेनिया जैसे खेल मुफ्त उपलब्ध रहेंगे।"

'वैक्सीनेशन के बाद अब आवारा कुत्तों को उनके मूल इलाकों में छोड़ा जाएगा', एससी का बड़ा फैसला

✷ **एनसीआर टुडे. नई दिल्ली** ✷

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम फैसला सुनाया है। इस फैसले को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन के बाद कुत्तों को उनके मूल इलाकों में ही छोड़ा जाएगा, लेकिन रेबीज (रेबीज) पीड़ित या आक्रामक कुत्तों को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

साथ ही, सड़कों पर कुत्तों को खाना खिलाने (फीडिंग) पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। इसके बजाय, नगर निगम (एमसीडी) को कुत्तों के लिए विशेष फीडिंग स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि व्यवस्थित तरीके से उनकी देखभाल हो सके।

कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही कुत्तों की फीडिंग की जाएगी। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया गया, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को फीडिंग करने की अनुमति नहीं दी है।

तीन जजों की बेंच, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया, ने यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही देशभर की सभी अदालतों में लंबित संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने का भी आदेश दिया गया है।

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था, लेकिन अब इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अदालत ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण यह समस्या बढ़ी है, इसलिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देशभर की अदालतों में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने से एकरूपता सुनिश्चित होगी और नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

बता दें कि 11 अगश्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को लेकर फिक्र जाहिर करते हुए एमसीडी और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) को तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया था।

अपने फैसले में कहा, "बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा

सुदर्शन रेड्डी ने उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया

✷ **एनसीआर टुडे. नई दिल्ली** ✷

उप राष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने गुरुवार को यहां गठबंधन के बड़े नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री रेड्डी सुबह संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राज्यसभा सचिवालय में महासचिव पी सी मोदी के कार्यालय में नामांकन करने के लिए पहुंचे। श्री मोदी इस चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी हैं।

श्री रेड्डी ने चार सेटों में नामांकन पत्र दायर किया। प्रत्येक सेट पर उनके समर्थन में 20 प्रश्तावकों और 20 अनुमोदकों ने हश्ताक्षर किये हैं। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, गठबंधन के वरिष्ठ नेता शरद पवार, रामगोपाल यादव और कई अनेक नेता भी मौजूद थे। उप राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। चुनाव में श्री रेड्डी का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सी पी राधाकृष्णन से है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में मतदान 09 सितम्बर को होगा।

श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, HC में सुनवाई आज

एनसीआर टुडे. मथुरा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुक्रवार दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई होगी।

जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ इस मामले को देख रही है। माना जा रहा है कि कोर्ट शुक्रवार को वाद के प्रमुख बिंदुओं को तय कर सकता है, जो इस विवाद के निपटारे में महत्वपूर्ण कदम होगा।

अलग-अलग थाना क्षेत्र से तीन अभियुक्त गिरफ्तार

एनसीआर टुडे. अलीगढ़ । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन द्वारा अपराध की रोकथाम एवं वांछित व वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अकराबाद पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त संजू पुत्र छोटेलाल निवासी कासिमपुर पडाव थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ को 18 टेट्रा पैकेट ट्विन टावर देशी शराब के पव्वा सहित एच0पी0 पेट्रोल पम्प के करीब 300 कदम पहले रोड के किनारे पर से गिरफ्तार किया। तो वहीं थाना अकराबाद पुलिस द्वारा एक वारन्टी अभियुक्त हरवीर सिंह पुत्र वीरपाल सिंह निवासी मै0 शिवम पब्लिक स्कूल उ0मा0 विद्यालय जसरथपुर जीटी रोड सिहोर थाना अकराबाद जनपद अलीगढ़ मूल निवासी ग्राम खुर्रमपुर थाना विजयगढ़ जनपद अलीगढ़ को शिवम पब्लिक स्कूल उ0मा0वि0 जसरथपुर से गिरफ्तार किया। तो वहीं थाना अतरौली पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र बीधाम्बर निवासी गनियावली थाना अतरौली जनपद अलीगढ़ को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया।

रिमोट सेंसिंग कार्यशाला कलेक्ट्रेट में आज

एनसीआर टुडे. अलीगढ़ । जिला अर्थ संख्या अधिकारी ए0के0 दीक्षित ने बताया है कि शनिवार 23 अगस्त को 12.30 बजे जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों द्वारा जीआईएस तकनीक का उपयोग करके जिले में तैयार किये गये डिजिटल डेटाबेस का प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया है कि वर्कशॉप में प्रतिभाग कर तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करें।

सात साल के बालक से कुकर्म, रोते हुए घर पहुंचा

एनसीआर टुडे. अलीगढ़ । युवक ने एक लड़के के साथ कुकर्म किया, आरोपी युवक भाग गया। पीड़ित ने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद गुरुवार को परिजनों ने थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की है। मामला गभाना थाना क्षेत्र का है। पीड़ित बालक के पिता ने कहा मैं मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला रहा हूं। गुरुवार दोपहर काम पर गया था। मेरी पत्नी और बच्चे घर पर थे। करीब दो बजे मेरा 7 साल का बेटा बाग के पास खेल रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाले युवक ने मेरे बेटे के साथ कुकर्म किया। पिता ने कहा बालक रोता हुआ अपनी मां के पास पहुंचा। उसने मां को पूरी जानकारी दी। जिसके बाद मां के होश उड़ गए। देर शाम मैं घर पहुंचा। पत्नी ने मुझे पूरे जानकारी दी। इसके बाद मैं बच्चे को लेकर थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। एसओ गभाना विनय कुमार के अनुसार आरोपी वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देर रात पीड़ित बालक को मेडिकल परीक्षण और इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया।

अस्पताल में युवक का सुसाइड, पत्नी से बोला सिर में दर्द दुपट्टा दो

एनसीआर टुडे. अलीगढ़ । थाना क्वार्सी इलाके के रामघाट रोड स्थित पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय के अंदर ग्रिल में फंदा डालकर युवक ने फांसी लगा ली। अस्पताल में फंदे से युवक का शव देख लटका देख लोगों में खलबली मच गई। सूचना पर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और मृतक के परिजन आ गए। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। आत्महत्या का कारण पुलिस पता करने में जुटी है। जानकारी के अनुसार जनपद बुलंदशहर के जहांगीराबाद का मूल निवासी अंशुल (35 साल) क्वार्सी क्षेत्र में परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था। जबकि होली चौक में उसकी साली अनुपम का परिवार रहता है। अनुपम पेट दर्द और बुखार के चलते पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में 19 अगस्त को वार्ड 9 में भर्ती हुई थी। 21 अगस्त की रात्रि में अंशुल अपनी साली अनुपम का हाल चाल लेने हॉस्पिटल गया था। वहीं, उसने अपनी पत्नी से सिर में दर्द का बहाना बनाकर दुपट्टा ले लिया और देर रात्रि वार्ड के पास से आने जाने वाले रास्ते में ग्रिल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी शुक्रवार की सुबह उस वक्त हुई जब हॉस्पिटल अस्पताल, मरीजों के तीमारदारों ने शव लटका देखा।

शरद पवार के पोते को बड़ी राहत

सहकारी बैंक घोटाले में रोहित को मिली जमानत

मुंबई, एजेंसी। मुंबई की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को शरद पवार के पोते और एनसीपी (एसपी) विधायक रोहित पवार को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में बड़ी राहत दी है। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया था। अदालत ने रोहित पवार को जमानत दे दी और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। हालांकि ईडी ने उनके और उनकी कंपनी बारामती एग्रो के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन जांच के दौरान उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।

विशेष न्यायाधीश एस.आर. नवंदर ने कहा कि मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पहले ही इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। न्यायाधीश ने कहा कि इस क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि मूल अपराध बंद कर दिया जाता है तो ईडी का मामला भी आगे नहीं बढ़ सकता। कोर्ट ने मामले की अगली

सुनवाई 8 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी है। ईडी ने इस क्लोजर रिपोर्ट का विरोध किया और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। विशेष लोक अभियोजक सुनील गोंसाल्वेस ने तर्क दिया कि या तो हस्तक्षेप की अनुमति दी जाए या इसे विरोध याचिका में बदला जाए। कृपया ध्यान दें कि ईओडब्ल्यू द्वारा की गई पूरी जांच मेरी जानकारी पर आधारित है। यदि हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाती है तो मेरे पास क्लोजर रिपोर्ट की कोई प्रति नहीं होगी, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं कर पाऊंगा। कोर्ट ने ईडी की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ईडी पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट में इसी तरह के खारिज किए गए मामले को चुनौती दे चुका है। न्यायाधीश ने कहा, आप हाईकोर्ट के सामने अपनी बात रखें। अदालत ने आपके लिए दरवाजा बंद कर दिया है। कोर्ट 18 सितंबर से ईओडब्ल्यू की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई शुरू करेगा।

वाराणसी में पार्किंग विवाद में शिक्षक की पीट-पीट कर हत्या

वाराणसी , एजेंसी। वाराणसी जिला मुख्यालय के भेलूपुर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर पार्किंग विवाद में एक निजी स्कूल के शिक्षक की ईंट और राड से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस उपायुक्त (अपराध) सरवन. टी ने बताया कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के मातृ अपार्टमेंट में रहने वाले शिक्षक डॉ प्रवीण झा (48) की बृहस्पतिवार रात पार्किंग को लेकर अपार्टमेंट में ही रहने वाले आदर्श सिंह से कहासुनी हो गयी। इसके बाद आदर्श ने अपने दो साथियों के साथ प्रवीण की ईंट और राड से पिटाई कर दी जिससे प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि परिजन तत्काल उन्हें ट्रामा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि परिजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने देर रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा कार्रवाई की जा रही है।

राजस्थान के अलवर में 50 लाख की स्मैक सहित दो तस्कर गिरफ्तार

अलवर, एजेंसी। राजस्थान के अलवर जिले की भिवाड़ी पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 50 लाख की स्मैक जब्त की है। पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस करवाई को भिवाड़ी पुलिस की मादक पदार्थ के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है।

भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण ने बताया की बुधवार रात चौपानकी थानाधिकारी द्वारा अजमेरी गेट पर नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों एवं व्यक्तियों की चैकिंग कर रहे थे । इसी दौरान रात 8 बजे अजमेरी गेट नाका पर एक मोटरसाईकिल आई, जिस पर दो युवक सवार थे।

पुलिसकर्मियों द्वारा हाथ का ईशारा कर चेकिंग के लिए बाइक को रुकवाना चाहा, लेकिन बाइक चालक पुलिस को चकमा देकर भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने बाइक का पीछा कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ा और भगाने का कारण पूछा, तो मोटरसाईकिल चालक सही जवाब नहीं दे पाए। इससे पुलिस को और भी शक होने लगा।

भिवाड़ी एसपी ने बताया की पकड़े गए दोनों युवकों की तलाशी ली, तो मौके से एक युवक के पजामे की जेब में पुड़िया में कुछ मिला। इस पर पुलिस ने दोनों के नाम पते पूछे, तो उन्होंने अपना नाम कमल (23) पुत्र ठाकुरचन्द निवासी शंकरपुरा थाना बुराड़ी दिल्ली तथा दूसरे शख्स ने अपना नाम कुलदीप (20) पुत्र ओमप्रकाश निवासी शंकरपुरा थाना बुराड़ी दिल्ली होना बताया।

दोनों युवकों को थाने पर लाकर सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया की इस पुड़िया में अवैध मादक पदार्थ स्मैक है। पुड़िया का वजन किया गया तो इसमें 259 ग्राम स्मैक निकली। इस पर पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अबॉर्शन कराने आई महिला की कर दी नसबंदी, नूंह के अस्पताल में डॉक्टरों का गजब कारनामा

नूंह, एजेंसी। हरियाणा के नूंह जिले में तावडू खंड स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों एवं स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों ने गर्भपात के लिए आई एक महिला की नसबंदी कर दी। महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की टीम ने मामले पर संज्ञान लिया और अस्पताल का निरीक्षण किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तावडू के सैनीपुरा की रहने वाली महिला के गर्भ में पल रहे दो माह का शिशु खराब हो गया था। वह पहले एक निजी अस्पताल गई थी। वहां पर डॉक्टरों ने गर्भपात के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गई। यहां पर डॉक्टर गर्भपात के लिए तैयार हो गए और उसे भर्ती कर लिया। डॉक्टरों ने गर्भपात के साथ उसकी नसबंदी भी कर दी। महिला ने यह बात अपने परिजनों को बताई। इस पर परिजनों ने आपत्ति जताई और नसबंदी को खोलने के लिए कहा है। चिकित्सकों ने खून की कमी का हवाला देते हुए नसबंदी खोलने से मना कर दिया और तीन महीने के बाद नसबंदी खोलने की बात कही। इस पर महिला के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पाकर महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की सदस्य सुमन राणा पहुंच गईं। उनके साथ गणेश कुमार, जिला बाल संरक्षण अधिकारी आबिद हुसैन, बाल कल्याण समिति चेयरपर्सन राजेश कुमार छौंकर, एमडीडी ऑफ इंडिया (शक्ति वाहिनी) से रीजनल कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र रावत समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने तावडू स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. निहाल सोलंकी को टीम गठित करके दो दिनों में रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए। डॉ. निहाल सोलंकी ने बताया कि तीन महीने बाद महिला की स्थिति को देखते हुए नसबंदी खोली जाएगी।

असम में अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड

गुवाहटी, एजेंसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को घोषणा की है कि अब राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फर्स्ट टाइम आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा। घुसपैठियों के मुद्दे पर लगातार हमलवार रहे मुख्यमंत्री हिमंत ने उन्हें देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। गुरुवार को उन्होंने कैबिनेट की एक अहम मीटिंग के बाद आधार कार्ड को लेकर घोषणा की है।

सरमा ने बैठक के बाद पत्रकारों से कहा है कि अगर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो उन्हें आवेदन करने के लिए केवल एक महीने का समय दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को छूट मिलेगी और उन्हें अगले एक साल तक आधार कार्ड मिलते रहेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत ने आगे कहा कि कुछ दुर्लभ मामलों में, एप्लीकेशन विंडो बंद होने के बाद भी जिला आयुक्त को आधार कार्ड जारी करने का अधिकार होगा। हालांकि जिला आयुक्त स्पेशल ब्रांच और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल रिपोर्ट की जांच के बाद ही कार्ड इश्यू कर सकेंगे। सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अवैध शरणार्थियों को, खास कर बांग्लादेशी नागरिकों को असम में आधार कार्ड प्राप्त करने और भारतीय नागरिकता का झूठा दावा करने से रोकना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य ने सीमा पर घुसपैठियों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया है और अब हमें किसी भी हाल में भारत की नागरिकता प्राप्त करने नहीं दिया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर कार-ट्रक में टक्कर; 3 लोगों की मौत, 3 घायल

ग्रेटर नोएडा , एजेंसी। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार देर रात हुए एक कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे का शिकार हुई कार में सवार सभी लोग हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे थे।घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची दादरी थाना पुलिस ने क्रेन व हाइड्रा की मदद से कार को काट-काटकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार, गुरुवार 21 अगस्त को थाना दादरी अंतर्गत अक्कबरपुर टोल प्लाजा के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक नंबर टीएस08 यूबी 7694 में एक कार वैगनार संख्या एचआर38 एटी 4379 पीछे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

यूपी में 2400, ताइवान में 12000 रुपये क्विंटल बिकता है मक्का

प्रयागराज के किसानों को मिला निर्यात ऑर्डर

प्रयागराज, एजेंसी। दुनिया के लोग संगमनगरी प्रयागराज के काला धान और अमरूद ही नहीं बल्कि मक्के का भी स्वाद चख सकेंगे। मक्के का वैश्विक बाजार तेज होने से प्रयागराज के मक्का किसानों को इसके लाभ मिलेंगे। पहली बार ताइवान को मक्के के निर्यात की मांग आई है। विदेशी व्यापारियों द्वारा मक्के की खरीद में रुचि से किसान काफी उत्साहित हैं। मक्का की उपज साल में तीन बार हो जाती है। कम समय में फसल तैयार

होने से ज्यादा आय की उम्मीद को देखते हुए किसानों का रुझान मक्का की खेती की तरफ बढ़ रहा है।

प्रयागराज के कृषि उप-निदेशक पवन कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि सरकार मक्के के बीज में 50 फीसदी की छूट दे रही है। प्रयागराज मंडल में 1461 हेक्टेयर में मक्का की खेती होती है। पिछले साल मंडल में 4418 मीट्रिक टन मक्के की पैदावार हुई थी। मक्के के निर्यात का प्रस्ताव फूलपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की ओर से आया है। मुंबई से ताइवान मक्का निर्यात करने वाले एक्सपोर्टर रणधीर सिंह मुन्ना की तरफ से जिले में पैदा होने वाले मक्के के निर्यात के लिए प्रस्ताव आया है। रणधीर सिंह मुन्ना ताइवान में मक्के के प्रमुख निर्यातकों में गिने जाते हैं।

मक्का उत्पादक उमेश पटेल बताते हैं कि उनके किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ) में 613 किसान हैं, जिनमें 221 महिला भी शामिल हैं। प्रदेश में मक्का लगभग 2400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जबकि एक्सपोर्ट में यह 8000 रुपये प्रति कुंतल तक बिक जाता है। वहीं, ताइवान में मक्के का भाव 12000 रुपये क्विंटल से ऊपर चल रहा है। उप-निदेशक पवन विश्वकर्मा के अनुसार 2025-2026 विपणन वर्ष के लिए सरकार ने रबी सीजन में मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रति क्विंटल 2225 रुपये घोषित की है। राज्य सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का खरीद रही है।

राजस्थान में यहां खुदाई के दौरान मिले डायनासोर के जीवाश्म जैसे अवशेष

जैसलमेर, एजेंसी। राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक गांव में डायनासोर युग के जीवाश्म मिले हैं। यहां पर एक तालाब की खुदाई चल रही थी, इसी दौरान बड़ी हड्डी के आकार का एक ढांचा और जीवाश्म जैसे कुछ अवशेष मिले। विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक डायनासोर का कंकाल हो सकता है। इससे इस जगह के प्रागैतिहासिक डायनासोर युग से जुड़े होने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि इनकी वैज्ञानिक पुष्टि होना अभी बाकी है, अब जीआईएस टीम इसकी वैज्ञानिक जांच करेगी। फतेहगढ़ उपखंड के मेघा गांव में एक तालाब की खुदाई करते समय लोगों को पत्थर की ये विशिष्ट संरचनाएं और बड़े कंकाल जैसा एक ढांचा मिला। इनमें से कुछ टुकड़े जीवाश्म लकड़ी जैसे हैं तो बाकी हड्डियां जैसे दिख रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में जीवाश्म लकड़ी असामान्य नहीं है, लेकिन हड्डी जैसी संरचनाओं की उपस्थिति इस खोज को विशिष्ट बनाती है। फतेहगढ़ के उपखंड अधिकारी व तहसीलदार ने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया और अवशेषों का निरीक्षण किया।

फतेहगढ़ के उपखंड अधिकारी भरतराज गुर्जर ने गुरुवार को पीटीआई-भाषा को बताया, हमने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (लद्दाख) के वैज्ञानिकों के जांच के लिए मौके पर आने की उम्मीद है।

हमर छत्तीसगढ़: पढ़ाई के साथ बच्चों की मुफ्त हेयर कटिंग, सैलून वाले गुरुजी तो कमाल हैं

कबीरधाम, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की बदहाली और शिक्षकों की लापरवाही की खबरें तो आपने बहुत देखी और सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सरकारी स्कूल के मास्टरजी यानी शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जो सैलून वाले गुरुजी के नाम से मशहूर हैं। चौंक गए न आप भी! दरअसल, कबीरधाम जिले के सरकारी मिडिल स्कूल में पदस्थ टीचर पूनाराम पनागर की पहल भी गजब है। यह शिक्षक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के साथ विद्यार्थियों के बाल भी नि:शुल्क कटिंग करते हैं। शिक्षक आखिर क्यों ऐसा करते हैं,नाई बनने के पीछे उनका क्या मकसद है तो चलिए आपको इस मास्टरजी के बारे में बताते हैं।

कौन हैं ये शिक्षक?: कबीरधाम जिले में बोड़ला स्थित पूर्व माध्यमिक स्कूल में शिक्षक पूनाराम पनागर की पोस्टिंग हैं। वह बच्चों को पढ़ाने के उनके बाल भी मुफ्त में काटते हैं। बाल कटिंग में खर्च होने वाले पैसों को शिक्षक बच्चों से कॉपी, पेन या स्कूल से संबंधी जरूरी काम करने को कहते हैं। शिक्षक पूनाराम बताते हैं कि मैं पहले बोड़ला के महलीघाट गांव के प्राइमरी स्कूल में था। इस आदिवासी क्षेत्र में सेलून नहीं थे। ऐसे में स्कूल के बच्चों के बाल काफी बढ़ जाते थे। तब मैने 2012 से खुद ही बच्चों के बाल काटना शुरू कर दिया। बाद में मेरा ट्रांसफर यहां बोड़ला के स्कूल में हो गया। यहां भी सरकारी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे गरीब परिवारों से है।

शिक्षक पूनाराम ने बताया कि सरकारी एससी-एसटी हॉस्टल के बच्चों के बाल महीने में किसी एक रविवार को काटता हूं। इससे बच्चों के सेलून का खर्चा बच जाता है। इतना ही नहीं शिक्षक पूनाराम सरकारी स्कूल के पहली से दसवीं क्लास के बच्चों

को 15 साल से स्कूल के अलावा फ्री कोचिंग भी दे रहे हैं। अपने पढाए बच्चों के बीच यह स्पर्धा भी कराते हैं कि जो जिले में टॉप करेंगे या प्रदेश में टॉपर सूची में आएंगे तो उन्हें 10 से 15 हजार इनाम भी देंगे। वे हर साल पर्चा छपवाकर इलाके में बंटवाते हैं कि लोग अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूल में ही कराएं। शिक्षक के इस पहल की पूरे प्रदेश में जमकर चर्चा हो रही है।

घर पर बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग भी पढ़ाते हैं: पूनाराम पनागर की इस पहल को सराहना न सिर्फ छात्र बल्कि अन्य शिक्षक और अभिभावक भी करते हैं। पूनाराम के काम को समाज सेवा की मिसाल मानते हैं। शिक्षक कृष्ण कुमार धुवे बताते हैं कि पूनाराम सर... बच्चों के शैक्षणिक उत्थान को लेकर बहुत सजग हैं। उनकी सोच यह है कि बच्चे पैसों की बचत करके उसका उपयोग शैक्षणिक गतिविधियों में करें। वे गरीब और कमजोर बच्चों को नि:शुल्क कोचिंग भी देते हैं, ताकि वे पीछे न रहें। अपने कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा भी करवाते हैं और यह भी कहते हैं कि 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले बच्चों को पुरस्कार भी अपनी जेब से देंगे।

सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने बांटते हैं पर्चा: कबीरधाम जिले में एक सरकारी शिक्षक अपनी सेवा भावना से मिसाल बन गए हैं। सरकारी स्कूलों में हर साल बच्चों का दाखिला घट रहा है, लेकिन शिक्षक पूनाराम हर साल खुद पर्चा छपवाकर ग्रामीणों से अपील करते हैं कि वे अपने बच्चों का दाखिला निजी स्कूलों में नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों में कराएं। महंगी फीस से बचें और उन पैसों को बच्चों के आगे की पढ़ाई के लिए बचाएं...। गरीब और कमजोर बच्चों को शिक्षक अपने पैसों से पुस्तक-कापी भी खरीदकर देते हैं, ताकि उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। ऐसे शिक्षक की प्रतिबद्धता ने यह साबित कर दिया है कि एक शिक्षक अगर चाहे तो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।

ट्रक की टक्कर से कार सवार तीन युवकों की मौत

✷ एनसीआर टुडे. ग्रेटर नोएडा ✷। कोतवाली दादरी क्षेत्र में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक की टक्कर से कार सवार तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे थे। घायलों का अलग-अलग अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने कार व ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश में लगी है। प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि कार सवार फरीदाबाद के खेड़ीपुर गांव निवासी लोकेश, छांयसा निवासी गौतम, हरविंदर, कुलदीप, कोसी कला के सुरवारी गांव निवासी गौरव और ललित हरिद्वार से फरीदाबाद लौट रहे थे। वह दादरी कोतवाली क्षेत्र में पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहुंचे तो उनकी कार और ट्रक की टक्कर हो गई। कार को लोकेश चला रहा था। टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रश्त हो गई। सभी लोग उसमें फंस गए। वहां से गुजर रहे लोगों ने घायलों को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन व हाइड्रा की मदद से कार को काट काटकर लोगों को बाहर निकाला। कार चालक लोकेश, गौरव और गौतम की मौके पर ही मौत हो गई। हरविंदर, कुलदीप और ललित गंभीर रूप से घायल हो गए। लोकेश कैब चलाता था। गौरव आइसक्रीम कंपनी में नौकरी करता था। वहीं, गौतम निजी कंपनी में नौकरी करता था। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने ट्रक और कार को कब्जे में ले लिया। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार चालक की तलाश में लगी है।

पंचायत सहायकों ने क्राप सर्वे कार्य से किए हाथ खड़े

✷ एनसीआर टुडे. नजीबाबाद ✷। विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सहायकों ने एग्रीस्टेक डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य करने से हाथ खड़े कर दिए हैं और इस कार्य से उन्हें मुक्त किए जाने की मांग की है, इसी को लेकर बड़ी संख्या में पंचायत सहायक शुक्रवार को नजीबाबाद खंड विकास कार्यालय पर पहुंचे जहा उन्होंने बीडीओ से मुलाकात की, पंचायत सहायकों ने दुखी मन से अपना दुखड़ा बीडीओ को सुनाते हुए कहा कि लेखपालों व अन्य विभागों का कार्य पंचायत सहायकों से कराया जा रहा है, एग्रीस्टेक क्रॉप सर्वे कृषि विभाग का है, जिसे जबरन पंचायत सहायकों पर थोपा जा रहा है, पंचायत सहायक जंगल व खेतों में नहीं जा सकते, वहा जंगली जानवरों का भी खतरा है, सर्वे के दौरान कुछ अनहोनी होने पर सरकार द्वारा कुछ भी देय नहीं है, उपरोक्त परेशानियों को देखते हुए सर्वे के कार्य से मुक्त किया जाए, पंचायत सहायकों ने सर्वे के कार्य को अपने कार्यक्षेत्र से बाहर बताया और इसे असंवैधानिक करार देते हुए इससे मुक्त किए जाने की मांग की। पंचायत सहायकों का छह हजार मानदेय है, जिसमे गुजरा नहीं हो रहा है जिसे बढ़ाया जाए, पंचायत सहायकों ने एक ज्ञापन बीडीओ को भी सौंपा।

हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिला कार्यकारिणी सदस्य बने नंदलाल

✷ एनसीआर टुडे. नगीना ✷। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 महंत श्री राजू दास ने जिला बिजनौर के नगीना निवासी हिंदूवादी नेता नंदलाल को संगठन का जिला कार्यकारिणी सदस्य बिजनौर नियुक्त किया। आपको बता दे कि हिंदू सुरक्षा सेवा संघ संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत राजू दास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बहुत ही करीबी संतों में से एक है। इसलिए संगठन को योगी आदित्यनाथ और पंडित धीरेंद्र शास्त्री का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है।

शिव धाम मंदिर में श्री कृष्णा की छठी पर्व धूमधाम से मनाई

✷ एनसीआर टुडे. नगीना ✷

भाद्र पक्ष में कृष्णपक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसके पश्चात छठे व सातवें दिन छठी पर्व मनाने की परंपरा है नगीना में शिवधाम मंदिर में छठी का पर्व बड़े उत्साह पूर्वक मनाया गया। आजाद कॉलोनी लाइन पार

कालाखेडी रोड नगीना में स्थित शिव धाम मंदिर में श्री कृष्ण का छठी पर्व धूमधाम से मनाया गया। छठी पर्व में पंडित रामगोपाल भट्ट द्वारा पूजा हवन किया गया।

मुख्य यजमान श्रीमती कमलेश शर्मा व उमेश चंद शर्मा तथा उनके दोनों पुत्र आशीष शर्मा तथा आकाश शर्मा सहपत्नी सहित उपस्थित रहे। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर भक्त जनों को कढ़ी चावल का प्रसाद वितरित किया गया।

हवन पूजन शिव धाम मंदिर के पुजारी श्री राम गोपाल भट्ट द्वारा संकल्प के साथ व धर्म के नियम अनुसार पूर्ण कराया गया।

छठी पर्व के कार्यक्रम में सी पी सिंह, प्रदीप कुमार, अखिलेश कुमार सिंह,धर्मेंद्र राठी, थमन सिंह, सुनील शर्मा, गर्वित चौधरी, राजकुमार शर्मा सपत्नी उपस्थित रहे।

इनके अलावा डॉ. अभय बिश्नोई, वीरेंद्र सिंह, लेखपाल, सुभाष चंद्र शर्मा, सुनील कुमार विशकर्मा, कृष्णदयाल शर्मा, संजय शर्मा, विशाल कुमार, पूर्व सभासद जोगिंदर सिंह, रामचरण सिंह, आकाश शर्मा, रवि सिंह, संजू शर्मा, संजीव कुमार, सुनील वेल्डिंग वाले, आशीष शर्मा, अनिल गुर्जर, बलिस्टर सिंह, विशाल चौहान, तुलाराम सिंह, गंगाराम झांसी वाले आदि कॉलोनी वासियों का संपूर्ण सहयोग रहा।

भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव आयोजित

✷ एनसीआर टुडे. नहटौर ✷

कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण छठी का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर महिला कीर्तन मण्डल ने भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया। बाल कृष्ण की झांकी को महिलाओं ने तिलक करके उपहार दिए।

मोहल्ला पूर्वी चौधरियान स्थित श्री शिव मंदिर परिसर में आयोजित छठी के कार्यक्रम में नगर कीर्तन मण्डल ने भजन कीर्तन के कार्यक्रम में धार्मिक भजनों को प्रशतुत करके कार्यक्रम को आकर्षक बनाया। साथ ही बाल रूप में बनी भगवान कृष्ण की झांकी का तिलक करके उपहार दिए।

चावल कढ़ी का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। समिति के पदाधिकारी अध्यक्ष नीरज कुमार, अरविन्द शर्मा, आशु कौशिक, रजनीश शर्मा, आशीष अग्रवाल, सोनू अग्रवाल, पुष्पेन्द्र शर्मा, बबलू त्यागी, सौरभमुनि त्यागी, ब्रह्म सिंह रवि, गगनदीप सिंह, राकेश चौहान राकेश दत्त शर्मा आदि गणमान्य नागरिकों व महिलाओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

बच्चे की मौत से मचा बवाल पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी

✷ एनसीआर टुडे. बिजनौर ✷

कोतवाली शहर क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 6 माह के बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही और एक्सपायरी इंजेक्शन लगाने का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया।

मामला बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

जानकारी के अनुसार नहटौर थाना क्षेत्र के हमीदपुर निवासी नितिन अपने छह माह के बेटे लवीश को डायरिया की शिकायत पर शहर के डॉ. ए.के. अग्रवाल के अस्पताल लेकर आए थे। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने बच्चे में खून की कमी बताते हुए ब्लड चढ़ाने की सलाह दी।

इसी दौरान बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आरोप है कि कंपाउंडर जगवीर ने इंजेक्शन लगाया, जो एक्सपायर था। परिजनों का कहना है कि कंपाउंडर नशे की हालत में था और इंजेक्शन की जांच करने पर पता चला कि वह जून में ही एक्सपायर हो चुका था। कुछ देर बाद बच्चे की मौत हो गई।

घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। सूचना पाकर पुलिस पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत कराया। परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

इस मामले में एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उधर, स्वास्थ्य विभाग को भी घटना की सूचना दे दी गई है। विभाग की एक टीम अस्पताल पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है।

नौकरानी ने पेशाब कर बरतानों पर छिडका, पुलिस कार्यवाही शुरू

✷ एनसीआर टुडे. नगीना ✷

थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक व्यापारी के घर में काम करने वाली महिला ने गिलास में पेशाब कर दिया, जिसकी पूरी करतूत घर में लगे कैमरे में कैद हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। व्यापारी ने इस संबंध में आरोपी महिला के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

बताया जा रहा है कि महिला पिछले करीब दस साल से व्यापारी के घर पर काम कर रही थी। घटना सामने आने के बाद व्यापारी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। शिकायत मिलते ही नगीना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना नगीना के एक मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता है। फिलहाल, पुलिस वीडियो और अन्य तथ्यों की जांच कर रही है।

इंस्पेक्टर धीरज नागर एच,एम,आई के छात्रों को साइबर जागरूकता, अनुशासन का पाठ पढ़ाया

✷ एनसीआर टुडे. नहटौर ✷

थाना प्रभारी धीरज नागर द्वारा एच एम आई इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं को साइबर जागरूकता तथा अनुशासन की आवश्यकता से अवगत कराया। नहटौर थाने के तेज तर्रार थाना प्रभारी धीरज कुमार द्वारा एच एम आई इण्टर कॉलेज नहटौर पहुंच कर छात्र-छात्राओं को संबोधित किया गया।

इस दौरान थाना अध्यक्ष द्वारा छात्र-छात्राओं से जीवन में अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई तथा साइबर जागरूकता के संबंध में छात्रों को अवगत कराया गया। उन्होंने छात्र-छात्राओं से नहटौर नगर में पुलिस की छवि के संबंध में प्रश्न पूछा तथा आश्वासन दिया की पुलिस छात्राओं की सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है। पीड़ित निसंकोच थाने जाकर अपनी बात रख सकते हैं।

लोनी में दुष्कर्म आरोपियों से मुठभेड़ दो आरोपी घायल, गिरफ्तार

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

लोनी थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।

निठौरा अंडरपास के पास हुई इस मुठभेड़ में आरोपी रोहित और वीर सिंह उर्फ भोला पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। दोनों आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।

पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। मुठभेड़ में घायल आरोपियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

इस मामले में पुलिस की शुरुआती कार्यवाही को लेकर स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने सवाल उठाए हैं। आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई में देरी की, जिससे पीड़िता और उसके परिवार को मानसिक यातना झेलनी पड़ी। इसके चलते क्षेत्र में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली।

मुठभेड़ के बाद गाजियाबाद पुलिस ने साफ किया कि गंभीर अपराधों में अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी और पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है।

इस कार्रवाई के बाद इलाके के लोगों में राहत का माहौल है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की सक्रियता की सराहना की और उम्मीद जताई कि इस तरह की कार्रवाई से आपराधिक घटनाओं पर रोक लगेगी।

मथुरा में इंटरेक्ट क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन की स्थापना

✷ एनसीआर टुडे. मथुरा ✷

मथुरा बाजना में रोटरी क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन इंटरनेशनल ने आर्केडियन पब्लिक स्कूल बाजना में भारत के प्रथम शैक्षिक संस्थान में विद्यार्थियों की इंटरेक्ट क्लब ऑफ ऑर्गन डोनेशन की स्थापना की। जिसमें रोटेरियन लाल गोयल चार्टर प्रेसिडेंट, इंस्पायरिंग प्रेसिडेंट रोटेरियन पी एच एफ रितिका गुप्ता, रोटेरियन चार्टर मेंबर अविनाश भार्गव आदि उपस्थित रहे।

सर्व प्रथम अतिथियों ने दीप प्रज्वल कर मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए उनके साथ विद्यालय के एकेडमिक डायरेक्टर एफ आर खान, प्रिंसिपल दलजीत सिंह नंदा जी भी रहे। रोटेरियन लाल गोयल ने विद्यार्थियों को अंग दान के महत्व के बारे में जानकारी दी और कहा कि लाखों लोग अंग फेल्यर होने के कारण जिंदगी की जंग हार जाते हैं हम ऑर्गन डोनेशन को इंटरनेशनल श्तर पर पूरी जिम्मेदारी से संचालन कर रहे है।

मथुरा की रोटेरियन प्रेसिडेंट रितिका गुप्ता ने 2025/26 के आर्केडियन पब्लिक स्कूल बाजना के विद्यार्थियों के इंटरेक्ट क्लब ऑर्गन डोनेशन की प्रेसिडेंट समायरा खान, सेक्रेटरी शिया, ट्रेज़री दिशा व अन्य क्लब के सदस्यों को बैंड पहनाकार जिम्मेदारी दी। लाल गोयल ने विद्यार्थियों से अंग दान से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जिनके जवाब को सुनकर हैरान थे।

विद्यार्थियों ने भी अंग दान से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न का जबाव लिया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ राजेंद्र सिंह सिसोदिया ने इस महान उद्देश आधारित क्लब की स्थापना विद्यालय में करने पर गहरी प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा अंग दान महा दान हैं जिससे लाखों लोगों के जीवन को बचाया जा सकता हैं।

आर्केडियन पब्लिक स्कूल बाजना के विद्यार्थियों के इंटरेक्ट क्लब ऑर्गन डोनेशन के सदस्यों को विद्यालय के सदस्य विवेक जिन्दल, ,अमित तिवारी, प्रकाश गौतम शालू अरोड़ा, सुची सिंघल , पदम कुमार और सुरेंद्र सिंह आदि उपस्थित रहे और क्लब के सदस्यों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती बलवंत चावला ने दिया।

इंदिरापुरम में मुठभेड़ के बाद लुटेरा घायल, 18 मुकदमों में वांछित आमिर कुरैशी गिरफ्तार

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

थाना इंदिरापुरम पुलिस ने बीती रात हिन्डन नहर की पुलिया के पास हुई मुठभेड़ में एक शातिर लुटेरे को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया।

पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद आमिर कुरैशी पर गाजियाबाद, हापुड़ और दिल्ली सहित कई जनपदों में लूट, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट और पुलिस मुठभेड़ जैसे 18 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आमिर लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें लगातार जारी थीं।

पुलिस टीम 21 अगश्त की रात हिन्डन नहर 5/6 की पुलिया पर संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कनावनी पुलिया की ओर से आ रहे एक बाइक सवार को रोकने की कोशिश की गई। खुद को घिरा देख आरोपी ने भागने का प्रयास किया और पीछा कर रही पुलिस टीम पर तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए और आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में गोली आरोपी के पैर में लग गई। मौके पर ही उसे दबोच लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मोहम्मद आमिर कुरैशी पुत्र आस मोहम्मद निवासी ईस्लामिया मदरसे के पीछे, थाना लोनी, जिला गाजियाबाद (वर्तमान पता चैनापुरी, थाना हापुड़ देहात, जनपद हापुड़) के रूप में हुई। उसकी उम्र लगभग 27 वर्ष बताई जा रही है।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की है। जानकारी के अनुसार बरामद बाइक के संबंध में थाना इंदिरापुरम में पहले से ही चोरी का मुकदमा दर्ज है।

सीओ अभिषेक श्रीवाश्तव ने बताया कि पूछताछ में आमिर ने कई वारदातों की स्वीकारोक्ति की है। उसने खुलासा किया कि वह गाजियाबाद, हापुड़ और दिल्ली में राह चलते लोगों से मोबाइल और चैन छीनता था और बाद में उन्हें दिल्ली में सश्ते दामों पर बेच देता था।

पुलिस का कहना है कि आरोपी इंदिरापुरम इलाके में एक और चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने की फिराक में आया था।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आमिर कुरैशी के खिलाफ गाजियाबाद, दिल्ली और आसपास के जिलों में डेढ़ दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब उसके बाकी आपराधिक नेटवर्क और साथियों की तलाश में जुटी है।

प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण आयोजित

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

देशमुख कुमार प्रभारी, राजकीय फल संरक्षण केन्द्र, गाजियाबाद ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि राजकीय फल संरक्षण केन्द्र द्वारा ग्रामीण बेरोजगार दूर करने हेतु युवक व युवतियों को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अन्तर्गत मुख्यमन्त्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के 2 दिवसीय खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण दिनॉक 21-08-2025 से दिनॉक 22-08-2025 तक ग्राम मकरमतपुर सिखैडा विकास खण्ड भोजपुर गाजियाबाद सम्पन्न किया गया जिसका शुभारम्भ ग्राम प्रधान श्री मोहित उपाध्याय और अरूण कुमार त्यागी बी०सी० केनरा बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

प्रधान द्वारा लाभार्थियो को लेखन सामग्री प्रशिक्षण किट वितरित कर किया, जनप्रतिनिधि के करकमलो द्वारा सरकार की इस महत्वाकाक्षी योजना से प्रशिक्षण प्राप्त कर खाद्य प्रसंस्करण की लघु/उध्यम इकाई स्थापित करने हेतु स्वरोजगार सृजन पर जोर दिया केन्द्र प्रभारी देशमुख कुमार द्वारा बताया की कम पूजी का निवेश कर स्वरोजगार के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने से दूसरे लोगो को भी रोजगार से जुडने का अवसर प्रदान होगा।

तीन बच्चों का बास्केटबॉल टीम में चयन, क्षेत्र में खुशी की लहर

✷ एनसीआर टुडे. नगीना ✷

शिक्षा के साथ खेलों में भी अपनी पहचान बनाने वाले सेंट मेरीज़ स्कूल के तीन छात्रों ने वह कर दिखाया है, जो किसी भी विद्यालय के लिए गर्व का अवसर होता है। कक्षा 12वीं 'ए' के विद्यार्थी चर्चित भारती, रूद्र चौहान और मन्थन विश्नोई का चयन आई.एस.सी. राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम में हुआ है।

इन तीनों खिलाड़ियों के चयन की खबर मिलते ही विद्यालय ही नहीं, पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई। युवा खिलाड़ियों ने मेरठ जोनल मुकाबले से अपने सफर की शुरुआत की, जहाँ शानदार प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई। इसके बाद आगरा में आयोजित अंडर-19 रीजनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भी टीम ने बाज़ी मारी और विजेता बनकर निकली। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन ने तीनों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में जगह दिलाई, जहाँ अब वे मेरठ टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

अपनी सफलता पर खिलाड़ियों ने विद्यालय के कोच नीरज सर, आलोक सर और शिवानी मैम को श्रेय देते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और अनुशासन ने ही उन्हें यह मुकाम हासिल कराया। साथ ही उन्होंने विद्यालय प्रबंधन समिति प्रधानाचार्य फादर शायजु, प्रबंधक फादर अनूप, व्यवस्थापक फादर नितिन और उप-प्रधानाचार्य सिस्टर जिस्मी के सहयोग और प्रोत्साहन को भी याद किया।

प्रधानाचार्य फादर शायजु ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा—"यह उपलब्धि न सिर्फ विद्यालय के लिए, बल्कि नगीना और पूरे जनपद के लिए गौरवपूर्ण है। इन छात्रों की मेहनत और लगन नई पीढ़ी को भी प्रेरित करेगी।विद्यालय परिवार और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

राखी पहलवान का आमरण अनशन, शिकायत करने के बाद पुलिस ही कर रही उत्पीड़न

✷ एनसीआर टुडे. गाजियाबाद ✷

महिला पहलवान राखी ने 22 अगश्त 2025 से गाजियाबाद जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना और आमरण अनशन शुरू कर दिया है। राखी ने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें बिना किसी कारण घर से निकाल दिया।

इस अपमानित कृत्य की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस प्रशासन भी उल्टे पीड़ित को लगातार धमकी दे रहा है। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है बल्कि लाखों महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए न्याय की लड़ाई है।

राखी ने अपनी प्रमुख मांगों को स्पष्ट करते हुए कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उनके मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने पुलिस की जवाबदेही तय करने की भी मांग की ताकि महिलाओं को धमकियों और अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति मिल सके। साथ ही उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनसे जुड़े मामलों में त्वरित व सुलभ न्याय प्रक्रिया लागू करने पर जोर दिया।

राखी का कहना है कि महिलाओं को वा श्त वि क सशक्तिकरण तभी मिलेगा

जब सरकारी योजनाओं का स ही क्रियान्वयन हो और परामर्श केंद्रों में फैले भ्रष्टाचार पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। अपने निजी जीवन की पीड़ा साझा करते हुए राखी ने बताया कि उनकी शादी 9 जुलाई 2024 को हुई थी।

शादी के कुछ ही समय बाद उनके पति विदेश चले गए और इसके बाद ससुराल पक्ष ने उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया।

राखी ने कहा कि वे तलाक नहीं चाहतीं, बल्कि परिवार में सम्मानपूर्वक जीवन बिताना चाहती हैं।

उनका कहना है कि एक महिला के लिए सम्मान और सुरक्षा ही सबसे बड़ा अधिकार है और वे इसी के लिए संघर्ष कर रही हैं।

इस आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों और महिला कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

राखी ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे अपने अनशन को और तेज करेंगी। उन्होंने समाज से अपील की है कि महिलाओं को समानता, सम्मान और सुरक्षा दिलाने के लिए सबको एकजुट होकर खड़ा होना होगा।

संपादकीय

सीमा पर चीन का दोहरा शिकंजा, ब्रह्मपुत्र पर भीमकाय बांध के बाद फास्ट रेल-ट्रेक

तिब्बत पर चीन का निरंकुश शासन और दृढ़ होगा तथा भारत के लिए खतरा और भयावह। चीन के पाकिश्तान का सबसे बड़ा और शक्तिशाली हितैषी होने से बांध और रेलपांत भारत की सुरक्षा और सार्वभौमिकता के लिए बड़ा खतरा हैं। बांध को लेकर दिल्ली को ढाका का सहयोग और विश्वास लेना चाहिये। जरूरी है कि अंतरदेशीय जल बंटवारे और प्रबंधन पर भारत और चीन के मध्य ठोस और सार्थक बातचीत हो।

खतरे की घंटियां लगातार घनघना रही हैं और उनमें कंपन पैदा किया है ड्रेगन यानि चीन ने। पाकिश्तान तक सीधा कारीडोर तलाशने के बाद से बीजिंग सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से भारत के लिये अकल्पनीय और भयावह मुसीबतें खड़ी करने की मुहिम में लिप्त है। दुनिया के छज्जे पर तेजगति की रेल पातें बिछाई जा रही है और विश्व की विशालतम नदियों में शुमार ब्रह्मपुत्र का पानी बांधा जा रहा है।

ये दोनों निर्माण चीन को सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली और सुदृढ़ पायदान पर खड़ा कर देंगे। दक्षिण पूर्व तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर पांच पनबिजली संयंत्रों को समेटे इस विशालतम बांध की बस कल्पना ही की जा सकती है। यह यांग्त्सी पर बने अब तक के विशालतम बांध थ्री गर्जेस से कई गुना बड़ा है। तिब्बत में 2015 में जल विद्युत परियोजना 1.5 अरब डॉलर की थी। यारलुंग जांग्बो परियोजना की लागत 167.7 अरब डॉलर है। 1.2 ट्रिलियन युआन की यह परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का हुलिया बदल देगी।

ब्रह्मपुत्र नदी बड़ा यू-टर्न लेकर बराश्ते अरूणाचल बांग्लादेश में प्रवेश करते हुये विश्व की सबसे गहरी घाटी का निर्माण करती है। वहां बांध बनने का अर्थ है ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह पर नियंत्रण। इससे हर साल 300 बिलियन किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। विश्व की छत रूपी तिब्बती पठार टेक्टॉनिक प्लेटों पर स्थित होने से अत्यंत संवेदनशील और भूकंप-संवेद है। भीमकाय बांध के निर्माण का सीधा अर्थ है भूगर्भ से छेड़छाड़। जाहिर है कि पर्यावरण प्रभावित होगा और पारिस्थितिकी भी।

इस हाहाकारी बांध के निर्माण को गत वर्ष दिसंबर में मंजूरी मिली। अरूणाचल से अनति दूर चीनी सीमा में निंगची में समारोह हुआ, जिसमें चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने शिरकत की। भारत और अन्य पड़ोसी राष्ट्रों की चिंताओं को खारिज कर द्रुतगति से निर्माण शुरू हो गया।

मीकांग नदी से चीन के सलूक के नतीजे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की स्मृति में है। ब्रह्मपुत्र पर बांध से भारत में अरूणाचल और बांग्लादेश-त्रिकूट (डेल्टा) सर्वाधिक प्रभावित होगा। असर लाओस, म्यांमार, वियेतनाम, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे अधोप्रवाही देशों पर भी पड़ेगा। बांग्लादेश की तबाही का खतरा सबसे ज्यादा है। 16 करोड़ की आबादी के बांग्लादेश की जल सुरक्षा, आर्थिकी, पर्यावरण और मृदा-उर्वरता पर इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसकी कृषि-समृद्धि की चूलें हिल सकती हैं।

धान उत्पादन में मिलियनों टन की कमी आयेगी, लेकिन मैत्री के बावजूद बीजिंग ने ढाका का नामचार की सूचनाएं दी। उसने 'नो-निगेटिव इंपैक्ट' का ढोल पीटा और 'बिल्ड फर्स्ट, निगोशियेट लेटर' की नीति अपनाई। ऐसा नहीं है कि भारत सशंक और सचेत नहीं है।

दिसंबर 24 में अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग ची से वार्ता में यह मुद्दा उठा। मगर भारत की चिंता को सबसे मुखर अभिव्यक्ति दी अरूणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने। उन्होंने ब्रह्मपुत्र पर चीनी बांध को 'वाटर बम' बताते हुए जीवन, भूमि और संसाधनों की तबाही की आशंका व्यक्त की और कहा कि प्रवाह पर नियंत्रण से चीन जब चाहे तब भारी मात्रा में पानी छोड़कर अरूणाचल में बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न कर सकता है।

यह तो हुई ब्रह्मपुत्र के पानी को बांधने की बात। अब आयें तिब्बत में रेलपोत पर। तिब्बत सन् 1950 तक दुर्गम क्षेत्र रहा है, लेकिन चीनी आधिपत्य के बाद वहां चीनियों का बड़े पैमान पर आव्रजन हुआ और अब वह चीन के कठोर नियंत्रण में है।

अब चीन किंघाई से ल्हासा तक दुनिया की सबसे ऊंची और तीव्र रेलपांत बिछा रहा है। 960 किमी लंबी यह पात 13123 फुट ऊंचाई पर होगी। इससे शिनिंग से ल्हासा पहुंचने में फकत 22 घंटे लगेंगे। करीब 90 फीसद रेलपॉत 300 मीटर ऊंचाई पर होगी। सन् 2018 में चेंगदू युआन और जून 2021 में न्यिंग्ची-ल्हासा के उपरांत युआन-न्यिंग्ची ट्रैक सन् 2030 तक पूरा होगा। इससे तांगगुला को 5068 मीटर ऊंचा होने से विश्व के सर्वोच्च रेलवे स्टेशन का दर्जा मिल जाएगा।

प्रारंभिक सिंचुआन जहां 300 मीटर ऊंचाई पर है, वहीं टर्मिनस सागर तल से 3000 मीटर ऊंचा ट्रेन यार्लुंग-त्सांग्पो घाटी से 16 बार गुजरेगी, जिसमें 47 बोगदे और 121 पुल निर्धारित हैं। यह रेल ट्रैक सबसे लंबी 42.5 किमी लंबी सुरंग को समेटेगा। 10 किमी लंबी मिलिन सुरंग को कठिनतम बोगदा माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट पर 320 बिलियन युआन की लागत आयेगी। इसे रेलपांत पर ट्रेन की गति होगी 100 किमी।

इसके पूर्ण हाने पर चीन के लिए तिब्बत पर नियंत्रण नागरिकों की आवाजाही, सैनिकों और आयुधों की तैनाती और फौजी ठिकानों की स्थापना आसान हो जायेगी। तिब्बत पर चीन का निरंकुश शासन और दृढ़ होगा तथा भारत के लिए खतरा और भयावह।

चीन के पाकिश्तान का सबसे बड़ा और शक्तिशाली हितैषी होने से बांध और रेलपांत भारत की सुरक्षा और सार्वभौमिकता के लिए बड़ा खतरा हैं। बांध को लेकर दिल्ली को ढाका का सहयोग और विश्वास लेना चाहिये। जरूरी है कि अंतरदेशीय जल बंटवारे और प्रबंधन पर भारत और चीन के मध्य ठोस और सार्थक बातचीत हो।

पंजाब में फंस रही है आम आदमी पार्टी

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

आम आदमी पार्टी पंजाब में लगता है दिन-प्रतिदिन दलदल में धंसती जा रही है। दिल्ली का अड्डा उखड़ जाने के बाद केजरीवाल ने अपने कुछ गिने चुने साथियों के साथ पंजाब में ही डेरा जमा लिया था। लेकिन केजरीवाल की लालसा दिल्ली, पंजाब से संतुष्ट होने वाली तो है नहीं। वे अपनी पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं मानते। उनकी दृष्टि में भाजपा के बाद उनकी पार्टी ही एक मात्र राष्ट्रीय पार्टी है।

वे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं। इस लिहाज से वे मोदी की टक्कर के नेता हैं। उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनना है। इसके लिए उन्हें और उनकी पार्टी को पैसे की जरूरत थी। दिल्ली में इसके लिए विशेष शराब नीति बनाई गई। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल मुफ्त। लेकिन जब हो हल्ला हुआ तो नीति को बीच राश्ते छोड़ दिया गया।

यह हो हल्ला कानून का ही था। कानून का हो हल्ला खतरनाक होता है। बीच राश्ते नीति छोड़ देने के बाद भी होता रहता है। यही कारण है कि केजरीवाल और उनके दूसरे साथी मनीष सिसोदिया को लंबे अरसे तक जेल में रहना पड़ा। अभी भी जमानत पर ही छूटे हुए हैं।

इससे भी ज्यादा नुकसान तो तब हुआ जब इस शराब घोटाले के कारण दिल्ली विधानसभा का चुनाव तक हार गए। उस हार की वजह से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पंजाब में डेरा जमा लिया। पहले केजरीवाल दिल्ली से छलांग लगा कर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और अब पंजाब से छलांग लगा कर प्रधानमंत्री का सपना पालने लगे। लेकिन दिल्ली में लगी पैसे की लत छूट नहीं रही थी। उसके लिए कोई राश्ता निकालना जरूरी था। पंजाब में इसके लिए एक नई नीति बनाई गई जिसका नाम रखा गया 'लैंड पूलिंग नीति'।

इस नई नीति के अनुसार सरकार को पांच-छह जिलों के किसानों की 65 हजार से भी ज्यादा उपजाऊ जमीन पंजाब सरकार ने काबू करनी थी। यह जमीन किसानों से लेकर बिल्डर्स को नई-नई कालोनियां बनाने के लिए दी जाने वाली थी। लेकिन ख़ूबसूरती यह थी कि इसके लिए किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाना था। किसानों को दिल्ली की शैली में समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आपको जमीन के बदले में एक या दो प्लाट दिए जाएंगे।

यानी मेरी एक एकड़ जमीन लेकर मुझे उसी जमीन में से एक प्लाट दिया जाएगा। इस प्लाट पर मैं दुकान खोल सकता था, घर बना सकता था। सरकार का कहना था कि इन प्लाटों की कीमत एक एकड़ की कीमत से कहीं ज्यादा होने वाली थी, क्योंकि अब यह प्लाट किसी विकसित कालोनी का हिस्सा बनने वाले थे।

यानी सरकार का कहना था कि यह खेती बेकार का काम था, किसानों को चाहिए कि वे नई विकसित कालोनियों में अपनी दुकानें खोलें और ख़ूब पैसा कमाएं। यह आम आदमी पार्टी की पंजाब में किसानों की भलाई के लिए लागू की जाने वाली किसान भलाई स्कीम थी।

दिल्ली में शराबियों के लिए 'शराब भलाई स्कीम' के फेल हो जाने के बाद पंजाब में यह नई 'किसान भलाई स्कीम' लागू की गई थी। लेकिन भीतर की बात जानने का दावा करने वाले कह रहे थे कि 'शराब भलाई स्कीम' की तरह ही यह पंजाब में बिल्डर्स माफिया से पैसा वसूलने का केजरीवाल का तरीका है।

लेकिन मान लो किसान अपनी जमीनें सरकार को देकर, खेती का काम छोड़ कर दुकानें भी खोल लें तो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बचता था। गांव में इस जमीन पर मजदूरी का काम काम करके आजीविका चलाने वाला भी एक वर्ग होता है। इसी जमीन के लिए किसानों की अन्य जरूरतें पूरी करने वाले कुछ बढ़ई, लोहार इत्यादि भी होते हैं।

किसान तो जमीन देकर दुकानदार बन जाएगा लेकिन किसान की जमीन पर आश्रित ये बाकी लोग कहां जाएंगे? इसका उत्तर देने की जरूरत शायद केजरीवाल जरूरी नहीं समझते। लेकिन पंजाब के किसान शायद केजरीवाल की

इस किसान भलाई स्कीम को समझ नहीं पाए। वैसे भी केजरीवाल की स्कीमों को समझने के लिए बुद्धि से ज्यादा चतुराई चाहिए। केजरीवाल को प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास व डां आनंद कुमार जैसे लोग नहीं समझ पाए थे। जब तक समझ पाते तब तक वे इन सभी को पार्टी से बाहर निकाल चुके थे।

जिस केजरीवाल की भीतरी चतुराइयों को अन्ना हजारे नहीं समझ पाए, उसे पंजाब के सीधे-साधे निश्छल किसान कहां समझ पाएंगे? यही सोच कर भगवंत मान की सरकार ने किसानों पर लैंड पूलिंग पालिसी का जाल फेंका था। लेकिन पंजाब का किसान समझ गया कि शिकारी ने जाल फेंका है।

पंजाब का किसान एक बार इस जाल में फंस चुका था और केजरीवाल को पंजाब में विधानसभा की 92 सीटें दे दी थीं। परंतु काठ की हांडी चूल्हे पर एक बार चढ़ती है, बार-बार नहीं चढ़ती। किसानों ने गांव के बाहर जगह-जगह बोर्ड लगा दिए, केजरीवाल की पार्टी का कोई आदमी गांव में न आए। उनका प्रवेश वर्जित है। भगवंत मान अपने चुटकुले सुना कर किसानों को धोखा देने की कोशिश करते करते स्वयं ही चुटकुला बनने की स्थिति में पहुंचने लगे। पहले तो वे अपने गांव की कहानियां सुनाया करते थे कि किसान अपनी जमीन की रक्षा के लिए कत्ल करने से भी नहीं चूकता, लेकिन अब वे यह समझाने लगे कि दुकानदारी के क्या क्या फायदे हैं। यह फायदे शायद उन्हें केजरीवाल ही बताते होंगे, क्योंकि भगवंत मान तो आज तक भी यही समझाते रहते थे कि किसान खेती कैसे करता है। लेकिन अब वे पंजाब के किसानों को नया पाठ पढ़ा रहे थे।

यह वह पाठ था जिसे याद करने में शायद भगवंत मान के भी पसीने छूट रहे थे। लेकिन किस्सा कोताह यह कि अंत में दिल्ली की शराब नीति की तरह पंजाब में यह किसान भलाई नीति भी सरकार को वापस लेनी पड़ी। आंखों में आंसू ला देने वाला प्याज भी खाना पड़ा और सजा भी भुगतनी पड़ी।

सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब के आगे आम आदमी का भीतरी पर्दा भी नंगा हो गया, हाथी के दांतों की तरह दो खाने के और होते हैं और दिखाने के लिए और होते हैं। पंजाब ने पहली बार केजरीवाल के खाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले असली तीखे दांत देखे थे। जाहिर है भरी सभा में किसी का पर्दा उठ जाए और उसकी असलियत सामने आ जाए तो उसे अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है। लैंड पूलिंग नीति का पर्दा खुल जाने के बाद यही चिंता केजरीवाल को सताने लगी।

कुछ महीनों बाद ही पंजाब विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। पार्टी के तीखे और खतरनाक दांत, जिनसे सचमुच खाया जाता है, लोगों ने देख लिए हैं। इसलिए आने वाले चुनावों में कहीं दिल्ली की तरह पंजाब भी केजरीवाल को अर्श से फर्श पर तो नहीं ले आएगा? यदि लैंड पूलिंग नीति के चक्कर में किसान फंस जाते तो चुनाव जीतने की संभावना बढ़ जाती। लेकिन उस नीति को तो किसानों ने छूने से भी इंकार कर दिया था।

अब चुनाव कैसे जीते जाएं? इसके लिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए नई नीति अपनाई। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, जिन्होंने पंजाब को संभाल लेने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक अंदरूनी बैठक में यह नई नीति समझाई।

उन्होंने कहा कि हमें हर हालत में पंजाब विधानसभा का आगामी चुनाव जीतना ही है। उनके अनुसार, '2027 का चुनाव जीतने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, सच-झूठ, प्रश्न-उत्तर, लड़ाई-झगड़ा, जो भी करना पड़ेगा, वह करेंगे। हम तैयार हैं जोश के साथ।' पंजाब में चुनाव जीतने के लिए उनकी इस भावी योजना पर वहां उपस्थित सभी तथाकथित कार्यकर्ताओं ने तालियां बजा कर इस नई नीति का स्वागत किया। पंजाब के लोगों को भी, एक प्रकार से चुनौती देते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब को लेकर अपनी इस नई नीति की घोषणा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर भी कर दी।

आम आदमी पार्टी के हौसले की तो सचमुच दाद देनी पड़ेगी। लगता है शराब नीति के बाद लैंड पूलिंग नीति और उसके बाद 'साम दाम दंड भेद नीति' के कारण केजरीवाल एक के बाद दूसरे दलदल में फंसते जा रहे हैं।

जब मुद्दा है राजनीतिक शुचिता का है तो विधेयक पर हंगामा क्यों?

ललित गर्ग

गंभीर आपराधिक आरोपों में घिरे नेता चाहे वे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री ही क्यों न हो, उनकी गिरफ्तारी या हिरासत के बाद एक निश्चित अवधि बीत जाने पर हटाने की व्यवस्था वाले विधेयक को जब केन्द्र सरकार ने लोकसभा में प्रश्तुत किया तो जरूरत से ज्यादा हंगामा एवं विरोध समझ में नहीं आया। इस तरह ईमानदार, अपराधमुक्त राजनीति एवं चरित्रसम्पन्न-पवित्र राजनेताओं की पैरवी वाले विधेयक पर हंगामा लोकतंत्र की गरिमा को आहत करता है।

गृहमंत्री अमित शाह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी ओर से इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रश्ताव रखा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार भी कर लिया, अब तो विपक्ष को विरोध एवं हंगामें को विराम देते हुए इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी ईमानदार, समानतापूर्ण एवं आदर्श व्यवस्था क्यों नहीं बननी चाहिए, जिससे उच्च पदों पर बैठे नेताओं के गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी अथवा हिरासत में लिये जाने पर उनके लिये पद छोड़ना आवश्यक हो जाये? आखिर इस आदर्श व्यवस्था में समस्या क्या है? क्यों विपक्ष नैतिक एवं आदर्श राजनीतिक व्यवस्था में अवरोधक बनकर अपने नैतिक चरित्र पर प्रश्न खड़े कर रहा है? क्या इस विधेयक का असर सत्तापक्ष के नेताओं पर नहीं होगा?

आजादी के बाद से कतितय राजनीतिक विसंगतियों के चलते राजनीति में अपराधी तत्वों का वर्चस्व बना रहा है। जनता यह अपेक्षा करती है कि जिन्हें वह अपना प्रतिनिधि चुनती है, वे अपराधमुक्त, निष्कलंक, ईमानदार और चरित्रवान हों।

परन्तु स्थिति इसके विपरीत दिखती रही है। एक ओर जनप्रतिनिधि अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं, दूसरी ओर वे पद से इश्तीफा देने या सार्वजनिक जीवन से दूर रहने के बजाय सत्ता की कुर्सी से चिपके रहते हैं। यही प्रवृत्ति जनता के विश्वास को तोड़ती है और राजनीति को संदेह के घेरे में डाल देती है।

यह प्रश्न अब और गंभीर हो उठा है कि क्या ऐसे व्यक्तियों को शासन और सत्ता के उच्च पदों पर बने रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या लोकतंत्र का आधार अपराध और भ्रष्टाचार पर खड़ा किया जा सकता है? निश्चित ही नहीं। जब तक राजनीति से अपराधी तत्वों का निष्कासन नहीं होगा, तब तक न तो सुशासन स्थापित हो सकता है न ही नया भारत, विकसित भारत एवं आदर्श भारत बन सकता है और न ही राजनीति के प्रति जनता का भरोसा लौट सकता है।

आज समय आ गया है कि नए कानून बनाकर राजनीति को अपराधमुक्त बनाने की दिशा में ठोस एवं कारगर कदम उठाए जाएं। यह केवल चुनाव सुधार का मामला नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा को बचाने का प्रश्न है। ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि जिस क्षण कोई जनप्रतिनिधि गंभीर अपराध में आरोपित होकर जेल भेजा जाए या आरोप सिद्ध होने तक हिरासत में रहे, वह स्वचालित रूप से अपने पद से मुक्त हो जाए।

इश्तीफे की प्रतीक्षा या राजनीतिक दबाव की आवश्यकता ही न रहे। अनेक नेताओं ने ऐसा आदर्श प्रश्तुत भी किया, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, झारखण्ड मुक्ति मोर्चा आदि अनेक पार्टियों के नेताओं ने जेल से सरकारें चलाने एवं मंत्री पद पर बने रहने के काले अध्याय रचे हैं, इसी के चलते इस नये विधेयक की अपेक्षा सामने आई।

भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में स्वच्छ राजनीति केवल आदर्श नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। जब सत्ता और शासन के केंद्र में अपराधी मानसिकता के लोग बैठते हैं, तो वे शासन को अपने स्वार्थ और अपराधों की ढाल बना लेते हैं। इससे न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था खोखली होती है, बल्कि आम जनता का जीवन भी संकट में पड़ता है।

भ्रष्टाचार, धनबल, बाहुबल, भाई-भतीजावाद, हिंसा और अनैतिकता का वातावरण उसी समय पनपता है, जब राजनीति अपराधियों के कब्जे में जाती है। ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले नेताओं की मांग आज पहले से अधिक बढ़ गई है।

जनता ऐसे नेतृत्व की तलाश में है जो अपने आचरण से उदाहरण प्रश्तुत करे। राजनीति यदि सेवा और त्याग का माध्यम बनेगी तो ही समाज का कल्याण होगा। जिन नेताओं पर जरा भी संदेह का धुंधलका हो, उन्हें स्वयं स्वेच्छा से पद छोड़ देना चाहिए। यही परंपरा राजनीति को उच्चता और गरिमा प्रदान कर सकती है।

अपराधमुक्त राजनीति केवल नैतिक अपेक्षा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूरी है। जब तक राजनीति में शुचिता और नैतिकता का स्थान नहीं बनेगा, तब तक सुशासन और ईमानदार प्रशासन की कल्पना अधूरी ही रहेगी। नए कानूनों का निर्माण कर अपराधियों के लिए राजनीति के दरवाजे बंद करना समय की सबसे बड़ी मांग है।

यह कदम न केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ करेगा, बल्कि जनता के भीतर यह विश्वास भी जगाएगा कि राजनीति वाश्तव में लोककल्याण के लिए है, न कि अपराधियों की शरणस्थली। यही अपराधमुक्त राजनीति का दर्शन है, जहां सत्ता अपराधियों का आश्रय-स्थल न होकर समाज की नैतिक ऊर्जा का केंद्र बने। यही उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है कि वह लोकतंत्र को उसकी वाश्तविक आत्मा लौटाए और राजनीति को सेवा, शुचिता और ईमानदारी का प्रतीक बनाए।

भारतीय लोकतंत्र में पिछले कुछ वर्षों से राजनीति और अपराध के गठजोड़ को लेकर गहरी चिंता लगातार उठती रही है। जनता बार-बार यह अपेक्षा करती है कि जिन्हें वे संसद और विधानसभा भेजते हैं, वे न केवल ईमानदार और पारदर्शी हों बल्कि उनके चरित्र और आचरण पर कोई दाग न हो।

किंतु बार-बार यही देखने को मिलता है कि गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे नेता भी उच्च पदों पर बने रहते हैं और शासन-सत्ता का उपयोग अपने बचाव के लिए करते हैं। इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया नया विधेयक (संविधान का 130वां संशोधन) एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है, केन्द्र सरकार इन विधेयकों को भ्रष्टाचार एवं अपराध विरोध बता रही है, जबकि विपक्ष इससे सहमत नहीं।

उनकी असहमति अनेक प्रश्नों को खड़ा कर रही है कि आखिर विपक्ष दागियों की वकालत करते हुए वह स्वयं भी दागी क्यों बन रही है? आशंका जताई जा रही है कि यदि यह संशोधन पारित हो गया तो विपक्ष-शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री अस्थिर हो सकते हैं, उनके पद संकट में पड़ सकते हैं।

दरअसल यह विरोध केवल विधेयक का नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक सुविधा, अपनी सत्ता बचाने और सुरक्षा का है। प्रश्न यह उठता है कि क्या विपक्ष वाश्तव में अपराधमुक्त राजनीति नहीं चाहता? क्या केवल सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति को अपराधियों का अड्डा बनाए रखना आवश्यक है?

विपक्ष का तर्क है कि सरकार इस विधेयक का दुरुपयोग कर सकती है, और केवल आरोप लगाकर भी नेताओं को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि लोकतंत्र में जब तक कानून कठोर और स्पष्ट नहीं होगा, तब तक राजनीति से अपराध का सफाया संभव नहीं है।

यदि किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप गलत सिद्ध होता है तो उसके लिए पुनः प्रतिष्ठा अर्जित करने के राश्ते खुले रहेंगे, परंतु गंभीर आरोपियों को शासन की कुर्सी पर बने रहने देना लोकतंत्र के साथ अन्याय है, उसकी मूल आत्मा को ध्वश्त करना है। ऐसा अरविन्द केजरीवाल ने पहली बार किया और जेल से ही सरकार चलाने का दम भरते रहे।

आज देश 'विकसित भारत' के संकल्प की ओर बढ़ रहा है। विकसित भारत का सपना केवल तकनीकी प्रगति या आर्थिक मजबूती से पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए स्वच्छ, ईमानदार और पारदर्शी राजनीति आवश्यक है। राजनीति में अपराधियों की घुसपैठ न केवल लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है बल्कि जनता के विश्वास को भी तोड़ती है।

अपराधमुक्त राजनीति न केवल आदर्श है बल्कि सुशासन और विकास की बुनियादी शर्त है। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे विधेयक का स्वागत किया जाए, क्योंकि यह राजनीति को शुचिता, नैतिकता और जनहित के मार्ग पर ले जाने का प्रयास है।

राजनीति में एक नये सूरज का उदय है। विपक्ष यदि इसका विरोध करता है तो यह सवाल स्वतः उठता है कि क्यों विपक्ष अपराधमुक्त राजनीति का विरोध करके अपराधियों का संरक्षण कर रहा है? क्या उसे अपने ही दागी नेताओं के लिए भय है? लोकतंत्र को बचाने और मजबूत करने के लिए यह विधेयक समय की मांग है।

नया भारत तभी विकसित भारत बनेगा जब उसकी राजनीति अपराधियों से मुक्ति होगी। अपराधमुक्त राजनीति से ही सुशासन आएगा, ईमानदार नेतृत्व पनपेगा और जनता के बीच विश्वास की नई रोशनी जगेगी। यही लोकतंत्र की असली जीत होगी।

प. बंगाल और असम में अल्पसंख्यकों की स्थिति में विरोधाभास

आशीष विश्वास

कुछ मायनों में, असम में आने वाली सरकारों को पश्चिम बंगाल सरकार की तुलना में अवैध आप्रवासन से निपटना कहीं अधिक कठिन लगा। असम और पूर्वोत्तर में जनसंख्या का स्वरूप, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी हैं और विभिन्न जातीय समूहों के बीच उनके धर्म के आधार पर अधिक विभाजन हैं, पश्चिम बंगाल की तुलना में कहीं अधिक जटिल है।

असम में भारतीय जनता पार्टी और प. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासन के बीच, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदायों के संबंध में दोनों राज्य सरकारों द्वारा अपनाई गई आधिकारिक नीतियां बिल्कुल अलग हैं।

आधिकारिक बयानों में आमतौर पर इश्तेमाल होने वाली नौकरशाही की भाषा/शब्दों से बचते हुए, यह कहा जा सकता है कि बंगाल में मुसलमान आमतौर पर असुरक्षित महसूस नहीं करते, जबकि असम में स्थिति बिल्कुल अलग है।

असम में, विभिन्न मीडिया रिपोर्टों और कई विशेष अध्ययनों के अनुसार, बहुसंख्यक मुसलमान भाजपा सरकार की हालिया नीतियों से ख़तरा महसूस करते हैं। असमिया भाषी मुसलमानों या अल्पसंख्यकों के अपेक्षाकृत समृद्ध नागरिकों को छोड़कर, गरीब बंगाली भाषी मुसलमान (स्थानीय भाषा में मियां) ही इन दिनों शिक्षा, रोज़गार के अवसरों और भूमि आवंटन से संबंधित मामलों में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का कड़ा विरोध कर रहे हैं।

जनसंख्या का यह बड़ा हिस्सा, जिसे कुछ हद तक कांग्रेस, अखिल भारतीय संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (एआईयूडीएफ) और कुछ राज्य-आधारित छोटे दलों का समर्थन प्राप्त है, अक्सर उच्च न्यायपालिका का रुख करता है और कथित पुलिसिया ज्यादतियों और भेदभावपूर्ण सरकारी उत्पीड़न से राहत की मांग करता है।

कई प्रभावशाली मानव संसाधन समूह कानूनी और अन्य तरीकों से उनके समर्थन में एकजुट होते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, दोनों ने असम में एक विशेष समुदाय के लक्षित वर्गों के प्रति अति-उत्साही या पूर्वाग्रही रवैये के लिए विभिन्न सरकारी विभागों को फटकार लगाई है। दिलचस्प बात यह है कि असम में मुसलमानों की आबादी अनुमानित 35प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 27 प्रतिशत है। दोनों राज्यों में, खासकर पूर्वी पाकिश्तान/बाद में बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले ज़िलों में, पिछले दशकों में मुस्लिम आबादी में असामान्य रूप से भारी वृद्धि हुई है।

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि केंद्र सरकार ने अवैध घुसपैठ की आशंका वाले क्षेत्रों की पहले से कहीं अधिक मज़बूती से सुरक्षा करने में अधिक पहल की और रुचि दिखाई है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ वर्षों में अवैध घुसपैठ के पैटर्न में बदलाव आया है - पचास और साठ के दशक में, हिंदू बड़ी संख्या में भारत आए, लेकिन बाद के दशकों में, कई मुसलमान अवैध रूप से भारत में घुस आए और बस गए।

कुछ मायनों में, असम में आने वाली सरकारों को पश्चिम बंगाल सरकार की तुलना में अवैध आप्रवासन से निपटना कहीं अधिक कठिन लगा। असम और पूर्वोत्तर में जनसंख्या का स्वरूप, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी हैं और विभिन्न जातीय समूहों के बीच उनके धर्म के आधार पर अधिक विभाजन हैं, पश्चिम बंगाल की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। स्वाभाविक रूप से, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के पास अन्य राज्यों के लोगों की तुलना में 'गैर-स्थानीय' लोगों की बढ़ती संख्या से परेशान और चिंतित होने के ज़्यादा कारण हैं, जो कुछ ही दशकों में उनके इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं और उनकी पुरानी संस्कृतियों को ख़तरा पैदा कर रहे हैं।

अवैध मुस्लिम घुसपैठ और बांग्लादेश से आए 'विदेशियों' द्वारा अपेक्षाकृत कम आबादी वाले इलाकों पर अवैध अतिक्रमण या पड़ोसी म्यांमार में अंतर-जनजातीय शत्रुता से ग्रश्त मणिपुर और मिज़ोरम जैसे राज्यों के प्रति उनके आक्रामक रवैये के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की आलोचना करना एक श्तर पर आसान है।

एक सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री के रूप में, स्वतंत्रता दिवस पर भी, हिमंता बिस्व शर्मा को 'अजनबियों के बारे में भड़काऊ बातें करते हुए सुनना वाकई चौंकाने वाला था, जिन्होंने कहा कि कुछ ही दशकों में वे असम पर कब्ज़ा कर लेंगे और शासन करेंगे! विभिन्न दलों और मीडिया के विभिन्न वर्गों ने जानबूझ कर लोगों में अलगाववाद का ज़हर फैलाने के लिए उनकी निंदा की।

लेकिन कहीं न कहीं, आलोचक शर्मा का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़े सवाल को नज़रअंदाज़ कर रहे हैः इस स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए - बस आंखें मूंदकर जनसांख्यिकीय बदलावों को बेरोकटोक जारी रहने दें या कुछ उपायों के ज़रिए क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करें, जिनसे कुछ लोगों को नाराज़गी हो भी सकती है और नहीं भी?

मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यों को देखते हुए, यह संदिग्ध लगता है कि श्री शर्मा अपने आलोचकों की ज़रा भी परवाह करेंगे। वे वही करते रहेंगे जो वे इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं - बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना अनुमति के मुस्लिम संपत्तियों को बुलडोज़र से गिराना। एक विश्लेषक का दावा है कि वे अपने विरोधियों को बस यह याद दिलाना चाहते हैं कि अगर राज्य ने अवैध घुसपैठ को रोकने के प्रति अधिक जागरूकता और दक्षता नहीं दिखाई, तो असम को लगभग एक दशक में अपना पहला गैर-असमिया मुख्यमंत्री मिलेगा।

'यह बात हमेशा राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने वालों पर भी कारगर साबित होती है। उन्होंने आगे कहा, 'और अब जब वे टीवी पर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचारों को देख रहे हैं, तो ज़्यादा लोग निजी तौर पर स्वीकार करेंगे कि शर्मा सही हैं, कांग्रेस या एआईयूडीएफ नेता नहीं।'

यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, फिर भी इसमें कोई दो राय नहीं कि श्री शर्मा गलत कारणों से कुछ समर्थन हासिल कर सकते हैं। अगर कोई इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर करता है, तो उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में फिर से कड़ी फटकार लग सकती है। दरअसल, उन्होंने पहले भी सार्वजनिक रूप से इससे भी बदतर बातें कही थीं और बच निकले थे। एक अनुभवी राजनेता होने के नाते, उन्हें जनता में नकारात्मक जातीय भावनाओं को बढ़ावा देने के खतरों का पूरा एहसास है, फिर भी उन पर लगाम लगाने वाला कोई नहीं है!

साथ ही, उनकी घृणित राजनीतिक शैली ने उन्हें चुनाव जीतने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में, भले ही कुछ हद तक विवादास्पद रूप से, एक अग्रणी नेता के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है। उनका असमिया बहुसंख्यक वोट बैंक और भी मज़बूत होता जा रहा है, और बंगाली हिंदुओं का एक वर्ग भी उन्हें वोट देता है। इसलिए, वे और पश्चिम बंगाल में उनकी कमज़ोर समकक्ष सुश्री ममता बनर्जी, खुलेआम अवसरवादी वोट बैंक-आधारित राजनीति में लिप्त हो सकते हैं। उन्होंने पहले भी मिश्रित आबादी वाले इलाकों में भाजपा की राष्ट्र-विरोधी नीतियोंÓ का विरोध करते हुए महिला मतदाताओं को, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया था, कई मौकों पर सीआरपी कर्मियों पर शारीरिक प्रतिरोध/हमला करने के लिए उकसाया है। श्री शर्मा की तरह, ऐसे भाषण बंगाल के चुनावों में उनकी लोकप्रियता और शक्ति को ही बढ़ाते हैं!

इससे अपरिहार्य निष्कर्ष यही निकलता है कि फिलहाल, दोनों राज्यों के प्रमुख समुदायों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह नियमित रूप से आयोजित बैठकें हों, सांस्कृतिक या खेल प्रतियोगिताएं हों या चुनिंदा क्षेत्रों में सकारात्मक सोच वाले युवाओं को आकर्षित करने के लिए छोटी-छोटी व्यापार/व्यावसायिक योजनाएं हों।

इसलिए, चाहे समाज को कुछ भी चाहिए हो, या समुदाय अपने लिए कुछ भी चाहते हों, श्री शर्मा और सुश्री बनर्जी जैसे नेता अपनी शक्ति और प्रसिद्धि को इसी तरह बढ़ाएंगे। श्री शर्मा मुसलमानों को कोसते हुए चुनाव जीतेंगे और सुश्री बनर्जी एक अलग तरह का व्यवहार करेंगी, जिसे कई लोग मुसलमानों का तुष्टिकरण मान सकते हैं, जिसमें कुछ मुसलमानों की असामाजिक गतिविधियों को नजरअंदाज करना भी शामिल है।

लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री राजनीतिक रूप से सही रुख अपनाती हैं और अपने भाषणों में हमेशा एक बेहद धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी चेहरा पेश करती हैं। हिमंता और ममता के बीच ज़मीन-आसमान का अंतर है, हालांकि दोनों ही अपनी-अपनी नीतियों के राजनीतिक लाभार्थी हैं।

आखिरकार, ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक लगातार बढ़ रहा है, और इसका श्रेय उन महिला मतदाताओं को जाता है जो 1200 रुपये के मासिक भत्ते के लिए अपनी उत्सुकता नहीं छिपातीं, जो उनके लिए एक बड़ी राहत है। अगर श्री शर्मा 'हिंदुत्व' की विचारधारा का पूरी तरह समर्थन करते हुए विवादास्पद राय व्यक्त करने में कूटनीतिक होने की ज़हमत नहीं उठाते, तो सुश्री बनर्जी अपनी हिंदू पृष्ठभूमि का बचाव करने और बंगाल में सभी हिंदू त्योहारों को प्रोत्साहित करने में ज़्यादा कूटनीतिक हैं।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती आशा शर्मा द्वारा 707 मंदाकिनी टावर सेक्टर -4, वैशाली गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) भारत से प्रकाशित एवं एन.सी.आर. प्रिंटर्स, 15/19 साइट-4, साहिबाबाद इंडस्ट्रीयल एरिया जनपद गाजियाबाद से मुद्रित। **संपादक** : संजय शर्मा
फोनः 9899683800 वेबसाइट : www.khabariya.com **ई-मेलः** todayncr@gmail.com >> ncrtoday@hotmail.com **RNI-UPHIN/2009/30721**

यूपी का हर व्यक्ति 37500 का कर्जदार

यूपी का हर व्यक्ति 37 पांच साल में राज्य का ऋण छह से बढ़कर नौ लाख करोड़ होने का अनुमान, 500 का कर्जदार

लखनऊ , एजेंसी। उत्तर प्रदेश में जहां बुनियादी और औद्योगिक विकास में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वहीं विभिन्न संस्थाओं से लिए उधार का बोझ भी बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष में अब तक यूपी के प्रत्येक व्यक्ति पर करीब 37500 रुपये का ऋण है। पांच साल में यूपी पर उधार 6 लाख करोड़ से बढ़कर 9 लाख करोड़ होने का अनुमान है।

राज्य वित्त आयोग के मुताबिक इसके बावजूद सरकार का राजस्व घाटा 2.97 फीसदी है जो आरबीआई की निर्धारित सीमा के अंदर है। यही वजह है कि पांच साल में बजट का आकार भी करीब दोगुना हो गया है। राज्य वित्त आयोग के मुताबिक राज्य के ऊपर उधार का बोझ विकास का संकेतक होता है, क्योंकि जितना ज्यादा खर्च

बुनियादी ढांचे के विकास पर होता है उतना ही ऋण बढ़ता है। शर्त ये है कि ये खर्च पारदर्शी और प्रबंधन नीति के तहत किया जाए। यानी ऋण का आकार नहीं, बल्कि उसका उपयोग और पुनर्भुगतान की योजना ज्यादा महत्वपूर्ण होती है।

अत्यधिक ऋण से विकासशील अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और ब्याज भुगतान में वृद्धि होती है। ऐसे में यूपी जैसे राज्य के लिए इसका संतुलन जरूरी है। वित्त आयोग के मुताबिक वर्ष 23-24 में राज्य सरकार पर कुल ऋण करीब 7.76 लाख करोड़ रुपये था जो वर्ष 25-26 में 9 लाख करोड़ रुपये के पार होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा वह स्थिति होती है, जब सरकार का कुल खर्च, उसकी कुल प्राप्तियों (ऋण को छोड़कर) से अधिक हो जाता है। यह घाटा इस बात का संकेत होता है कि सरकार को अपने खर्च पूरा करने के लिए कितनी उधारी की जरूरत पड़ी। दूसरे शब्दों में, राजकोषीय घाटा सरकार की वित्तीय जरूरतों और संसाधनों के बीच का अंतर दर्शाता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार कितना खर्च अपनी आय से नहीं, बल्कि उधारी से कर रही है। अगर यह घाटा लगातार अधिक बना रहता है, तो इससे सरकार पर ऋण और ब्याज का बोझ बढ़ता है। हालांकि, सीमित और नियंत्रित राजकोषीय घाटा हमेशा नकारात्मक नहीं होता। यदि सरकार इस उधारी का उपयोग सड़क, बिजली, जल, शिक्षा और स्वास्थ्य अवसंरचना आदि पर करती है तो इससे आर्थिक विकास होता है और राजस्व बढ़ता है। यूपी का वित्त वर्ष 2025-26 में अनुमानित राजकोषीय घाटा 91400 करोड़ है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.97त्न है। यह घाटा केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत निर्धारित 3 फीसदी की सीमा के भीतर है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है।

क्राइम सीन से कोर्ट तक, हर सबूत संभालेगी हाईटेक फोरेंसिक वैन

प्रयागराज , एजेंसी। अपराध की हर परत खोलने और वैज्ञानिक तरीके से जांच को पुख्ता करने के लिए जनपदीय पुलिस को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से तीन दिन पहले हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई हाईटेक फोरेंसिक वैन प्रयागराज पहुंच चुकी है। इस वैन के जरिये पुलिस को घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में न केवल आसानी होगी बल्कि अपराधियों तक पहुंचने का रास्ता भी तेजी से खुलेगा।

मोबाइल लैब की तरह करेगी काम: अफसरों का कहना है कि यह फोरेंसिक वैन दरअसल मोबाइल लैब की तरह काम करेगी। अपराध स्थल पर पहुंचकर मौके पर ही सबूतों को सुरक्षित करने, उनका प्रारंभिक परीक्षण करने और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से सील करने की सुविधा वैन में मौजूद रहेगी। अब तक जहां टीमों को नमूने लेकर प्रयोगशालाओं में भेजने पड़ते थे, वहीं नई वैन में कई मामलों में मौके पर ही टेस्टिंग की सुविधा मिल सकेगी।

परिवार परामर्श केन्द्र ने तीन परिवारों को टूटने से बचाया

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में पारिवारिक समस्याओं व मतभेदों के मामलों को परिवार परामर्श केन्द्र में काउंसलरों द्वारा दोनों पक्षों को साथ बैठाकर उनकी समस्याओं को सुनकर तीन जोड़ों के समझौते कराकर उनके परिवारों को टूटने से बचाया। शुक्रवार को परिवार परामर्श केंद्र में कुल तीन पारिवारिक मामलों का सफल निश्तारण किया गया, पहला मामला थाना क्वार्सी की रहने वाली सकीना (परिवर्तित नाम) तथा बुलंदशहर के रहने वाले फारुख इकबाल (परिवर्तित नाम) का था, दूसरा मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले किशोरी (परिवर्तित नाम) तथा राजन कुमार (परिवर्तित नाम) का था, तीसरा मामला थाना सासनी गेट, अलीगढ़ की रहने वाली बिंदिया (परिवर्तित नाम) एवं राया मथुरा के रहने वाले भूषण (परिवर्तित नाम) का था। इन सभी मामलो में परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी उपनिरीक्षक श्रीमती शिखा त्यागी एवं काउंसलर बृजेश मिश्रा ने परामर्श देकर पक्षकारों के बीच आपसी सुलह समझौता कराया, परिणामस्वरूप सभी दंपतियों ने पुराने मतभेद भुलाकर सहमति से साथ रहने का निर्णय लिया।

बासमती चावल की शुद्धता के लिए जिले में 11 कीटनाशक रसायनों पर रोक

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। बासमती चावल में कीटनाशक अवशेषों के खतरे को देखते हुए जिले में कुछ रसायनों के प्रयोग, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से 60 दिनों की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदेश श्तर से जारी अधिसूचना के अंतर्गत ट्राईसाइक्लाजोल, बुप्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरपाइरीफास, हेक्साकोनोजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथाक्साम, प्रोफेनोफास, इमिडाक्लोप्रिड, कार्वोफ्यूरॉन एवं कार्वेण्डाजिम जैसे कीटनाशक रसायनों के किसी भी प्रकार के फार्मूलेशन का प्रयोग बासमती चावल में नहीं किया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी धीरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि इन रसायनों के उपयोग से चावल में अधिकतम अवशेष श्तर (एमआरएल) बढ़ जाता है, जिससे यूरोपीय संघ, अमेरिका और खाड़ी देशों जैसे बड़े आयातक देशों में निर्यात प्रभावित होता है। वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में बासमती चावल के निर्यात में 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। एपीडा (भारत सरकार) एवं सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ ने भी गुणवत्तायुक्त और बाधा-मुक्त निर्यात सुनिश्चित करने के लिए इस पाबंदी का समर्थन किया है और विकल्प स्वरूप एकीकृत रोग प्रबंधन (आईडीएम) पद्धति अपनाने की संश्तुति की है। जिला कृषि अधिकारी धीरेंद्र कुमार चौधरी ने जिले के समश्त कृषक भाइयों से अपील की है कि बासमती चावल की खेती में उपरोक्त प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग कतई न करें। यह कदम प्रदेश की गौरवशाली बासमती उपज की अंतरराष्ट्रीय श्तर पर प्रतिष्ठा बनाए रखने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। बासमती चावल की फसल में ट्राईसाईक्लाजोले, बुप्रोफेजिन, एसीफेट, क्लोरपाइरीफास, हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, थायोमेथाक्साम, प्रोफेनोफास, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बोफ्यूरान एवं कार्बेण्डाजिम जैसे कीटनाशकों का 60 दिनों तक प्रयोग, बिक्री व वितरण प्रतिबंधित है।

उत्कृष्ट सेवा के लिए जेएन मेडिकल कालिज की नर्स सम्मानित

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज (जेएनएमसीएच) के पीडियाट्रिक ट्रॉमा यूनिट की सिस्टर इंचार्ज निसार जहां को कुपोषण से मुकाबले में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए बाल विकास एवं पोषण विभाग, अलीगढ़ द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। यह सम्मान अतरौली ब्लॉक के सलेमपुर गोवर्धन गांव में आयोजित विशेष पात्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान दिया गया। जहां को कुपोषित बच्चों की नर्सिंग देखभाल और समय पर चिकित्सा की सुनिश्चित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सराहा गया। अलीगढ़ मंडलायुक्त श्रीमती संगीता सिंह ने उन्हें प्रशशित पत्र प्रदान किया। विभागीय अधिकारियों ने जहां और उनकी टीम की धैर्य, विवेकशीलता और समर्पण की सराहना की, जिसकी बदौलत कई नन्हें जीवन बचाए जा सके। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा समाज के प्रति गहरी जिम्मेदारी को दर्शाती है। स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके कार्यों ने न केवल बच्चों को नया जीवन दिया, बल्कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में नई उम्मीद भी जगाई है। विभाग द्वारा जारी प्रशशित पत्र में उनकी निःस्वार्थ सेवा को दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बताया गया और यह विश्वास दोहराया गया कि समर्पण और कर्तव्यपरायणता समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के शक्तिशाली साधन हैं।

विकसित होंगी नगर पालिकाएं, गौरव पथ... स्मार्ट क्लास रूम व ईवी स्टेशन के साथ बढ़ेंगी डिजिटल सेवाएं

लखनऊ । राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की समीक्षा की। उन्होंने जिला मुख्यालयों स्थित नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित बनाने की योजना के क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया। कहा कि स्मार्ट-विकसित नगर पालिका योजना का उद्देश्य पालिकाओं को आधुनिक, आत्मनिर्भर और नागरिक-केंद्रित रूप में विकसित करना है।

इस योजना तहत नगर पालिकाओं में गौरव पथ, पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लास रूम व आंगनबाड़ी, थीम आधारित पार्क, ऐतिहासिक धरोहर संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, ईवी चार्जिंग स्टेशन, ग्रीन क्रेमेटोरियम और डिजिटल सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए उत्सव भवन, सामुदायिक केंद्र और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आधारित ढांचे भी स्थापित किए जाएंगे।

सेवाओं में आधुनिकता आएगी... संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस योजना को हब-एंड-स्पोक मॉडल पर लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लखनऊ और गोरखपुर स्थित एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से समीपवर्ती जिलों की नगर पालिकाओं को जोड़ा जा सकता है। इससे सुरक्षा, निगरानी और शिकायत निवारण जैसी सेवाओं में आधुनिकता आएगी। साथ ही संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

अधिकारियों ने बताया कि नगर निकायों को चार करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक का अनुदान देने का प्रस्ताव है। यह उनकी जनसंख्या और कार्य दक्षता पर आधारित होगा। बैठक में लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर संचालित करने तथा अन्य नगरों में 650 बसों की प्रत्यक्ष खरीद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी शीघ्र तैयार किया जाए।

पीपीपी मोड पर परियोजनाएं शुरू करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि 74वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप नगर निकायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार मिलने चाहिए। लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आजाद अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज एवं बहुउद्देशीय खेल परिसर की स्थापना के भी निर्देश दिए। उन्होंने इन परियोजनाओं को पीपीपी मोड पर प्राथमिकता के साथ शुरू करने के लिए कहा।

शिवसेना नेता प्रियंका बोलीं- संविधान संशोधन लोकतंत्र के खिलाफ साजिश, सीबीआई और ईडी हो रहा दुरुपयोग

अयोध्या , एजेंसी। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद और शिवसेना (उद्धव गुट) की वरिष्ठ नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अयोध्या पहुंच कर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने श्रीराम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली बताया। कहा कि भगवान रामलला की कृपा देश और लोकतंत्र पर बनी रहे।

अयोध्या की धरती से प्रियंका चतुर्वेदी ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा। कानून संशोधन को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया। मोदी सरकार द्वारा संसद में जाए गए संविधान संशोधन विधेयक को उन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया। कहा कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। इनका दुरुपयोग हो रहा है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए किया जा रहा है। एक साल बाद क्लीन चिट दी जाती है। सवाल तो उठेंगे ही। बिहार चुनाव पर भी प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा दावा किया उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी। जनता सत्ता पक्ष से नाराज है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अयोध्या में विकास के साथ रोजगार उपलब्ध कराने की भी मांग रखी।

सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा पर लगा गुंडा एक्ट, भूमाफिया संजय राना पर भी कार्रवाई

बरेली , एजेंसी। बरेली में बारादरी थाना पुलिस ने सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अविनाश मिश्रा और पीलीभीत बाईपास गोलीकांड के आरोपी भू माफिया राजीव राना के भाई संजय राना पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। अविनाश मिश्रा फरीदपुर के मोहल्ला कानूनगोयान का मूल निवासी है और फिलहाल कोतवाली के सिविल लाइन इलाके में रहता है। वह सपा जिला उपाध्यक्ष समर्थ मिश्रा का भाई है।

छात्र नेता के तौर पर चर्चित अविनाश के खिलाफ मारपीट, रंगदारी वसूलने जैसे कई मुकदमे हैं। उसके भाई समर्थ मिश्रा के खिलाफ भी कई मुकदमे हैं। समर्थ ने आगामी चुनाव में कैंट विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी के तौर पर दावा ठोंक रखा है। हाल ही में सपा के कैंट विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रोहित राजपूत की पिटाई मामले में समर्थ और अविनाश पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। शहर के संजय नगर निवासी संजय राना को फायरिंग कांड का मास्टरमाइंड बताया जाता है। प्लॉट के विवाद में हुए गोलीकांड में करीब पौन घंटा पीलीभीत बाईपास पर फायरिंग हुई थी। इसके वीडियो देश भर में वायरल हुए थे। तत्कालीन एसएसपी सुशील घुले का इसी वजह से तबादला हो गया था। भू माफिया राजीव राना के बाद अब उसके भाई संजय राना पर कार्रवाई की गई है।

अलीगढ़ जिला 26वें स्थान पर सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷

जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जुलाई माह की सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि अलीगढ़ जिला प्रदेश में 26वें स्थान पर रहा।

जिलाधिकारी ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यह सभी विभागीय अधिकारियों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है। उन्होंने उत्कृष्ट प्रगति दर्ज करने वाले अधिकारियों को बधाई दी और उन्हें निरंतर बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, विशेषकर ग्रामीण विकास, नियोजन एवं लोक निर्माण विभाग, वे अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं और तय समय सीमा में लक्ष्यों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि शिथिलता किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है और सभी विभागीय अधिकारियों को विकास कार्यों को गति देकर बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने होंगे।

समीक्षा बैठक का संचालन डीएसटीओ ए0के0 दीक्षित ने किया। उन्होंने बताया कि नेडा द्वारा 3288 के सापेक्ष 2272 प्रतिस्थापन किए गए हैं। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ, बीएसए एवं डीआईओएस को कहा कि अन्तर्विभागीय समन्वय से प्रगति को बनाए रखें। डीएचओ शालिनी तोमर एवं क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी अनुपम श्रीवाश्तव बैठक से बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर मुख्य विकास अधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यह स्थिति कई बैठकों से देखने को मिल रही है, जो अनुचित है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़ें और यदि किसी अन्य जिले में अतिरिक्त चार्ज है तो उसकी सूचना भी बैठक से पूर्व उपलब्ध कराई जाए।

जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग को निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं खराब ट्रांसफार्मरों का समयबद्ध प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एनआरएलएम की समीक्षा में रैंक 23 से घटकर 49 होने पर उन्होंने डीसी मंजू त्रिपाठी से कड़ी नाराजगी जताई और सीसीएल में सुधार लाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री आवास योजना में गलत फीडिंग पाए जाने पर अतरौली के बीडीओ को कार्य सुधारने के लिए निर्देशित किया गया। मनरेगा में मानव दिवस सृजन कम होने पर डीसी मनरेगा अनुज सक्सेना को कार्य सुधार कर मानव दिवस सृजित कराने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सभी बीडीओ ग्रामीण समस्याओं के निश्तारण में गंभीरता दिखाएं, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाने की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

सीएमओ ने बताया कि अब तक 37,200 कार्ड बनाए जा चुके हैं, जबकि लक्ष्य के सापेक्ष अभी काफी कार्य शेष है। डीएम ने बीडीओ एवं एडीओ को इसमें सक्रिय सहयोग करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के नियमों को पंचायत सचिवालयों पर वाल राइटिंग कराने, प्राथमिक विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर जल संयोजन सुनिश्चित करने और फैमिली आईडी निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

सीडीओ ने बीडीओ अतरौली एवं गोंडा को कार्य में सुधार करने और अन्यथा की दशा में चार्ज हटाए जाने की चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्यों में तेजी लाने, अधिकाधिक मानव दिवस सृजन कराने, मत्स्य संपदा योजना में अधिक पट्टा आवंटन सुनिश्चित करने और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए क्रय होने वाले बर्तनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

साथ ही सिंचाई विभाग को नदी पुनरुद्धार कार्ययोजना तैयार करने के आदेश दिए। बैठक में गौवंश संरक्षण, कृत्रिम गर्भाधान एवं सहभागिता योजना के लक्ष्यों को भी समयबद्ध पूरा करने पर बल दिया गया।

अधिवक्ता के ड्रेस में कोर्ट पहुंचकर हत्या के आरोपी ने किया सरेंडर, पुलिस को चकमा देकर हुआ हाजिर

प्रयागराज , एजेंसी। मऊआइमा में सर्राफा कारोबारी अमन कुमार सोनी की हत्या के मुख्य आरोपी प्रेम पटेल ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। क्राइम ब्रांच की तीन टीमों और स्थानीय पुलिस की एक टीम को चकमा देकर आरोपी अधिवक्ता की ड्रेस में कोर्ट में हाजिर हो गया। पुलिस की टीमें हाथ मलती रह गईं। अदालत ने न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया। घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा था। पुलिस की कई टीमें उसकी खोजबीन में लगी थीं। मऊआइमा में 17 अगस्त को दिनदहाड़े सर्राफा कारोबारी को चाकू से गला काट कर हत्या कर दी गई थी। शव को एक नहर में फेंक दिया गया था। मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम मानी उमरपुर रमना (कोहरान) परवलपुर निवासी अमन कुमार सोनी (20) वर्ष पुत्र अजय कुमार सोनी ग्राम बाराडीह में सर्राफा की दुकान किया था। रविवार को दिन में करीब ग्यारह बजे के करीब वह बाइक से दुकान जा रहा था। बताया गया है कि अमन कुमार सोनी जैसे कलुआपुर और हरखपुर स्थित नहर पुलिया के पास पहुंचा पहले से घात लगाकर बैठे तीन युवकों ने चाकुओं से गला काट कर हत्या कर शव नहर में फेंक दिए। राहगीर घटनास्थल की ओर दौड़े लेकिन तब तक आरोपी भाग गए। एक आरोपी शुभम पटेल पुत्र राम सेवक को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था।

उर्वरक संकट के खिलाफ सपा का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

बहराइच , एजेंसी। जिले में उर्वरक संकट के खिलाफ बृहस्पतिवार को सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर तीन सूत्री ज्ञापन एडीएम अमित कुमार को सौंपा। चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो जनांदोलन शुरू किया जाएग।

पार्टी जिलाध्यक्ष राम हर्ष यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कार्यालय से जुलूस निकाला। जुलूस कलेक्ट्रेट पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो गया। वक्ताओं ने यूरिया की कालाबाजारी, बाढ़ व कटान से विस्थापित किसानों की समस्या और चिलवरिया चीनी मिल से गन्ना किसानों के सौ करोड़ का भुगतान न होने के मामले को उजागर किया। इस मौके पर देवेश चंद्र मिश्रा, उत्तम सिंह, अनिल यादव, रामजी यादव, तारिक खां, अवधेश वर्मा, सुंदरलाल बाजपेयी, मनुदेवी, सुमन शर्मा, मंजू चौधरी, नंदेश्वर नंद यादव, नदीमुलहक तन्नू, अनवर खां वारसी, राजे मिर्जा, रक्षाराम यादव व अमरदीप यादव आदि मौजूद रहे।

50 लाख से अधिक लागत की परियोजनाओं की समीक्षा, डीएम ने लगाई फटकार

✷ एनसीआर टुडे. अलीगढ़ ✷

कलैक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में 50 लाख से अधिक लागत वाली निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पाया गया कि सड़क परियोजनाओं को छोड़कर कुल 84 कार्यों में से 11 पूर्ण हुए हैं जबकि 73 अभी अधूरे पड़े हैं।

वहीं 16 सड़क परियोजनाओं में से 3 पूरे हो चुके हैं और 13 पर कार्य प्रगति पर है। जिले में विभिन्न निर्माण कार्य कराने वाली एजेंसियों में राजकीय निर्माण निगम द्वारा 2, सी एंड डीएस 9, यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन 9, यूपी सिडको 1, आवास विकास एवं लोक निर्माण विभाग के भवन निर्माण, प्रांतीय और निर्माण खण्डों द्वारा 3-3, जल निगम नगरीय 9, पैकफेड 10, ग्रामीण अभियंत्रण 7 एवं सिंचाई विभाग द्वारा

8 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान मल्टीलेवल कार पार्किंग का निर्माण कार्य दिसंबर मासांत तक एवं डीडीयू में क्रिटिकल केयर यूनिट का कार्य सितंबर मासांत तक पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया। पर्यटन विभाग की सभी परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन को निर्देशित किया गया। आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण में हो रही देरी पर जिलाधिकारी ने यूपी सिडको के अधिशासी अभियंता को कड़ी फटकार लगाते हुए संस्था को ब्लैकलिस्ट करने एवं सेंटेज काटने के निर्देश दिए।

उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि कार्य में लेट-लतीफी पर ठेकेदारों के खिलाफ अब तक क्या अर्थदंड लगाया गया है और 30 सितंबर तक हर हाल में कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया। इसी क्रम में लोनिवि निर्माण खण्ड के अधिशासी अभियंता ए0के0 राही को आरएमपीएसयू का निर्माण जल्द से जल्द समाप्त करने के साथ ही बेहतर लैंडस्केपिंग कर उत्कृष्ट श्तर की हरियाली विकसित करने के निर्देश दिए गए।

नगर क्षेत्र में संचालित सभी कार्यों को जनवरी-फरवरी तक पूरा करने को कहा गया। इसके अलावा सीएलडीएफ को सभी गौ-आश्रय स्थलों का निर्माण तथा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को कश्तूरबा गांधी विद्यालयों के कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

डीएम ने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा होना अनिवार्य है।

बैठक में सीडीओ प्रखर कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन पंकज कुमार समेत कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं संबंधित विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

28 बॉल में 102 रन... मारे 10 छक्के

इंग्लैंड के दो बल्लेबाजों ने रचा इतिहास

नई दिल्ली, एजेंसी। नीता अंबानी की टीम इस समय इंग्लैंड में धमाल मचा रही है. उसने द हंड्रेड लीग में जीत का पंजा लगा लिया है और पॉइंट्स टेबल के टॉप पर बनी हुई है. इस लीग के 23वें मुकाबले में नीता अंबानी की टीम ओवल इनविंसिबल्स एक समय काफी मुश्किल में फंसी हुई थी. टीम को जीत के लिए 40 गेंदों में 102 रन बनाने थे, लेकिन इंग्लैंड के दो बल्लेबाजों ने केवल 28 गेंदों में ही मैच को खत्म करके इतिहास रच दिया. इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 छक्के जड़े.

इससे 11 गेंद शेष रहते नीता अंबानी की टीम ने शानदार जीत दर्ज कर ली. द हंड्रेड लीग के 23वें मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स ने 100 गेंद में सात विकेट पर 171 रन बनाए. 172 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीता अंबानी की टीम ओवल इनविंसिबल्स की ने धीमी शुरुआत की, लेकिन जॉर्डन कॉक्स और सैम करन के मैदान पर आते ही रनों की बारिश होने लगी. इन दोनों बल्लेबाजों ने 42 गेंदों 96 रन जोड़कर टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया. अंत में कॉक्स और डोनोवन फरेरा (14) ने तेजी से रन बनाते हुए 11 गेंद शेष रहते टीम को 6 विकेट से जीत दिला दी. 24 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स ने 32 गेंदों में 4 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 58 रन बनाए. सैम करन ने केवल 24 गेंदों में 6 छक्के और 2 चौकों की मदद से 54 रनों की तेज पारी खेली. ट्रेंट रॉकेट्स की ओर से रेहान अहमद ने सबसे ज्यादा दो विकेट लिए. डेविड विली और बेन सैंडरसन को एक-एक विकेट मिला. इससे पहले ट्रेंट रॉकेट्स ने ओवल इनविंसिबल्स के खिलाफ तेज शुरुआत की.

➤ ट्रेंट रॉकेट्स ने की तेज शुरुआत

ओवल इनविंसिबल्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए ट्रेंट रॉकेट्स ने तेज शुरुआत की. टॉम बैंटन (9) और जो रूट ने पहले विकेट के लिए केवल 28 गेंदों में 55 रन जोड़ दिए. टॉम बैंटन के आउट होने के बाद रूट ने रेहान अहमद (28) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और टीम का स्कोर 100 रन के पार कर दिया. इसके बाद टीम की पारी लड़खड़ा गई, लेकिन एक छोर से जो रूट तेजी से रन बनाते रहे. उन्होंने 41 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्का की मदद से 76 रनों की पारी खेली. अंत में जॉर्ज लिंडे ने 8 गेंदों में 1 चौका और 3 छक्के की मदद से तेजी से 25 रन बनाए, जिसकी मदद से ट्रेंट रॉकेट्स ने 100 गेंद में 7 विकेट पर 171 रनों का स्कोर खड़ा किया. ओवल इनविंसिबल्स की ओर से राशिद खान और टॉम करन ने दो-दो विकेट लिए. जेसन बेहरेनडॉर्फ और नाथन सॉटर को एक-एक विकेट मिला.

इंडिया-पाकिस्तान:

पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय खेल संबंध नहीं रखना सही फैसला

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने कहा कि सरकार खेलों को प्रोत्साहित करना चाहती है लेकिन देश सबसे पहले आता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट की अनुमति देकर लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती। खेल मंत्रालय द्वारा भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय खेल टूर्नामेंट पर रोक लगाने और केवल बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं की अनुमति देने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में खडसे ने पत्रकारों से कहा, ''इन दिनों हमारे संबंध जिस तरह के हैं, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, मुझे लगता है कि यह एक अच्छा फैसला है। '' उन्होंने कहा, हमारे लिए देश बहुत महत्वपूर्ण है। हम खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे देश से खिलाड़ियों को लाकर अपने लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। हमारे लिए देश और उसके लोग पहले आते हैं। इसलिए यह एक बहुत अच्छा फैसला है। डल झील में शुरू हुए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए यहां आईं रक्षा खडसे ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब देश की 'वाटर स्पोर्ट्स' राजधानी बनने की क्षमता है।

रविचंद्रन अश्विन ने अब बताई अचानक रिटायरमेंट की असली वजह

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय स्पिन दिग्गज रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बीच रिटायरमेंट लेने पर खुलकर बात की. अश्विन ने पूर्व कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत में ये बात बताई. अश्विन ने कहा- विदेश दौरों पर टेस्ट मैचों से बाहर बैठना मुझे बहुत खलने लगा और यही मेरी अचानक इंटरनेशनल रिटायरमेंट की वजह रही. अनिल कुंबले के बाद 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज अश्विन ने सभी को चौंकाते हुए पिछले दिसंबर ब्रिस्बेन में तीसरे टेस्ट के बाद संन्यास की घोषणा कर दी थी.

अपने यूट्यब चैनल पर बात करते हुए अश्विन ने राहुल द्रविड़ से कहा- मैं काफी उम्रदराज हो चुका था, ये मानता हूं, लेकिन बार-बार टूर पर जाना और ज्यादातर बाहर बैठना, मुझे बहुत खलने लगा था.

ऐसा नहीं था कि मैं टीम में कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर आप सोचने लगते हैं कि क्या घर पर बच्चों के साथ समय बिताना बेहतर है. वो भी बड़े हो रहे हैं और मैं यहां बैठा क्या कर रहा हूं? तो मैंने महसूस किया कि बस अबज मेरे मन में हमेशा था कि 34-35 की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा. लेकिन बीच में लगातार न खेल पाने की वजह से फैसला कर लिया.

यूपी टी-20 लीग:

15 चौके-छक्के... रिंकू सिंह ने 45 गेंदों में ठोका शतक

नई दिल्ली, एजेंसी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला. उन्होंने केवल 45 गेंदों में 225 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए तूफानी शतक ठोककर अपनी टीम को शानदार जीत दिला दी. इस दौरान उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके लगाए. एक समय 38 रनों पर चार विकेट गंवा चुकी मेरठ माविरक्स को कप्तान रिंकू सिंह ने मुश्किल से निकाला और सात गेंद शेष रहते टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई.

रिंकू सिंह ने इस दौरान मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाकर एशिया कप से पहले अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज करा दी है. लखनऊ के इकाना स्टेडियम में क्क टी20 लीग का नौवां मैच गोरखपुर लायंस और मेरठ माविरक्स के बीच खेला गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए गोरखपुर लायंस ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 167 रन बनाए. 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मेरठ माविरक्स की शुरुआत काफी खराब रही और उसके चार बल्लेबाज केवल 38 रन पर आउट हो गए.

विश्व कुश्ती चैंपियनशिप:

अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में काजल स्वर्ण के लिए खेलेंगी

समोकोव (बुल्गारिया), एजेंसी। स्वप्निल शशांक युवा भारतीय पहलवान काजल ने दो बड़े स्कोर वाली जीत दर्ज करते हुए बृहस्पतिवार को अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के महिलाओं के 72 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया, जबकि श्रुति और सारिका सेमीफाइनल में हारने के बाद कांस्य पदक के लिए भिड़ेंगी। मौजूदा अंडर-20 एशियाई चैंपियन और 2024 कैडेट विश्व चैंपियन काजल ने अपने तीन मुकाबलों में दो बार दोहरे अंक हासिल किए।

उन्होंने एमिली मिहाइलोवा अपोस्टोलोवा को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 15-4 से हराकर शानदार जीत हासिल की। इसके बाद किर्गिस्तान की कैयरकुल शारशेबायेवा को क्वार्टर फाइनल में 7-0 से हराकर एक और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अमेरिका की जैस्मीन डोलोरेस रॉबिन्सन के खिलाफ काजल ने 13-6 से जीत दर्ज की। श्रुति ने महिलाओं के 50 किग्रा भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए प्री-क्वार्टर फाइनल में वायलेटा बिरियुकोवा पर 5-4 की जीत से शुरुआत की और फिर पोलैंड की अन्ना यात्स्केविच पर 4-0 की शानदार जीत दर्ज की, लेकिन वह जापान की रिना ओगावा की बराबरी नहीं कर सकीं और सेमीफाइनल तकनीकी श्रेष्ठता से हार गईं।

सारिका ने 53 किग्रा भार वर्ग में दबदबा बनाया। उन्होंने सेवल केयर को तकनीकी श्रेष्ठता (12-2) से हराया। इसके बाद सारिका ने चीन की तियानयु सुन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में एक भी अंक नहीं गंवाया और 8-0 से जीत हासिल की, पर सेमीफाइनल में वह यूक्रेन की अनास्तासिया पोल्स्का से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हार गईं। ग्रीको रोमन पहलवान सूरज ने 60 किग्रा वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी लेकिन वह अर्मेनिया के युरिक मखितार्यन से तकनीकी श्रेष्ठता से हार गए जिससे अब वह कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। प्रिंस (82 किग्रा) क्वार्टर फाइनल में हार गए लेकिन रेपेशेज के जरिये कांस्य पदक की दौड़ में बने हुए हैं। रीना (55 किग्रा) और प्रिया (76 किग्रा) फाइनल में पहुंच चुकी हैं। दोनों दिन के अंत में स्वर्ण पदक मुकाबलों में प्रतिस्पर्धा करेंगी। तपस्या (57 किग्रा) पहले ही स्वर्ण और सृष्टि (68 किग्रा) रजत पदक जीत चुकी हैं।

एशिया कप से बाहर, अब BBL के जरिए टी20 क्रिकेट में वापसी करना चाहेंगे बाबर आजम

कराची, एजेंसी। पाकिस्तान के सुपरस्टार और सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल चुके बाबर आजम को अगर इस प्रारूप में एक और अंतरराष्ट्रीय मैच खेलना है तो बिग बैश लीग का इस्तेमाल अपनी टी20 बल्लेबाजी सुधारने के लिए करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका दौरे के

बाद से कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। इस प्रारूप में देश के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी होने के बावजूद बाबर को अगले महीने यूएई में होने वाले टी20 एशिया कप के लिए नहीं चुना गया।

पाकिस्तान के कोच माइक हेसन ने कहा कि बीबीएल सिक्सर्स के इस बहुमूल्य खिलाड़ी के लिए अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाने और स्पिन के खिलाफ अपनी बल्लेबाजी को निखारने का एक मौका था। हेसन ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि बाबर को स्पिन का सामना करने और अपने स्ट्राइक रेट के मामले में कुछ क्षेत्रों में सुधार करने के लिए कहा गया है। बाबर जैसे खिलाड़ी के पास क्क्क में खेलने और टी20 में यह दिखाने का मौका है कि वह इन क्षेत्रों में सुधार कर रहा है। ये वो चीजें हैं जिन पर वह वाकई कड़ी मेहनत कर रहा है।

वह इतना अच्छा खिलाड़ी है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबर ने 128 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 129.22 के स्ट्राइक रेट से 4223 रन बनाए हैं। उनके रिकॉर्ड में 39 इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए 50 प्लस का स्कोर बनाया है। 2023 में सिर्फ 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलकर बाबर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 146.06 का स्ट्राइक रेट हासिल किया। हालांकि पिछले साल इनमें से 24 मैच खेलने के बाद 2024 के लिए बाबर का स्ट्राइक रेट घटकर 133.21 रह गया। हेसन ने बाबर की वापसी की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तानी कोच ने स्वीकार किया कि टीम प्रबंधन ने उन खिलाड़ियों को चुनने पर ध्यान केंद्रित किया है जिन्होंने देश की हालिया टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा, साहिबजादा फरहान ने छह मैच खेले हैं और तीन बार प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। इस समय हमारे पास जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया में बाबर ने 13 टी20आई मैच खेले हैं और 114.85 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 286 रन बनाए हैं।

हालांकि सिडनी सिक्सर्स के सभी प्रशंसकों का आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात यह है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान के इस दिग्गज खिलाड़ी को कुछ सफलता मिली है।

वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का रंगारंग आगाज, पहले दिन जम्मू-कश्मीर ने जीता सोना; यूपी-ओडिशा भी चमके

श्रीनगर, एजेंसी। डल में तीन दिन चलने वाले इस खेल महाकुंभ के पहले दिन जम्मू-कश्मीर के मोहसिन अली ने कयाकिंग के-1, 1000 मीटर (पुरुष) स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का वीरवार को रंगारंग आगाज हो गया। डल में तीन दिन चलने वाले इस खेल महाकुंभ के पहले दिन जम्मू-कश्मीर के मोहसिन अली ने कयाकिंग के-1, 1000 मीटर (पुरुष) स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश के विशाल कुमार ने कैनोइंग सी-1, 1000 मीटर (पुरुष) और ओडिशा की रश्मिका साहू ने कैनोइंग सी-1, 200 मीटर (महिला) स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के बैक लॉन में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का वीरवार को रंगारंग शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री रक्षा निखिल खडसे, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला शामिल हुए। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में देशभर से 409 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं।

700 करोड़ की डील के बाद लिया गया फैसला? हुआ बड़ा खुलासा

बदला जाएगा मुंबई इंडियंस की टीम का नाम

मुंबई, एजेंसी। मुंबई इंडियंस फ्रैंचाइजी विदेशों में भी खूब सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है. कुछ सप्ताह पहले ही एमआई फ्रैंचाइजी ने द हंड्रेड लीग की ओवल इन्विंसिबल्स टीम में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है. अब एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ओवल इन्विंसिबल्स को एमआई लंदन नाम से जाना जाएगा. यह नया नाम अगले सीजन से लागू होगा. बता दें कि ओवल इन्विंसिबल्स ऐसी छठी टीम बनी थी, जिसका मालिकाना हक मुंबई इंडियंस के पास है. द हंड्रेड सीजन 2026 से पहले ओवल इन्विंसिबल्स का नाम बदल कर एमआई लंदन कर दिया जाएगा. 2025 सीजन शुरू होने से पहले द हंड्रेड टीमों की कम से कम 49 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए बोली लगनी शुरू हुई थी. इनमें से एमआई फ्रैंचाइजी ने ओवल इन्विंसिबल्स टीम के लिए बोली लगाई थी, जिसकी वैल्युएशन 123 मिलियन पाउंड्स बताई गई थी. चूंकि मुंबई इंडियंस ने 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है, जिसके लिए उसे करीब 60 मिलियन पाउंड्स से ज्यादा रकम चुकानी होगी. जो भारतीय मुद्रा में करीब 700 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी.

आईसीसी ने जारी किया नया शेड्यूल, चिन्नास्वामी स्टेडियम से छीनी गई वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी

आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान मची थी भगदड़

इंडियन प्रीमियर लीग2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की खिताबी जीत के बाद एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में विक्ट्री परेड हुई थी. इस विक्ट्री परेड के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोग मारे गए थे. साथ ही 50 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे. इस वाकये के बाद जस्टिस जॉन माइकल डीकुन्हा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ, जिसने अपनी जांच में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए असुरक्षित माना.

नई दिल्ली, एजेंसी। आईसीसी ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है. अब इस वर्ल्ड कप के दौरान बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबले नहीं खेले जाएंगे. एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैचों को अब नवी मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है. नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम में अधिकतम पांच मैच खेले जाएंगे. इनमें तीन लीग मैच, एक सेमीफाइनल और संभवतः 2 नवंबर को महिला क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का खिताबी मुकाबला भी शामिल है. अगर फाइनल में पाकिस्तानी टीम पहुंचती है तो ही मुकाबला कोलंबो के आर.प्रेमदास स्टेडियम में होगा. बता दें कि बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम को अनसेफ घोषित किया गया था. आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन 30 सितंर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में किया जाना है. डीवाई पाटिल स्टेडियम के अलावा एसीए स्टेडियम (गुवाहाटी), होल्कर स्टेडियम (इंदौर), एसीए-वीडीसीए स्टेडियम (विशाखापत्तनम) और आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) में मुकाबले खेले जाएंगे.